RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 343 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 11-07-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 ‘सहकार से समृद्धि’ की मिसाल बना राजस्थान : शर्मा

6 यूपी वक़्फ़ बोर्ड में हिन्दुओं की एंट्री ‘ऐतिहासिक न्याय’

7 फिल्म निर्माण में उतरेंगी सना सईद

फर्स्ट टेक

पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक विमान का मलबा मिला

कराची/भाषा। पाकिस्तान की तलाश एवं बचाव टीमों ने शुक्रवार को उस मालवाहक विमान के मलबे के और हिस्से बरामद किए, जो इस सप्ताह के शुरु में अरब सागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के दौरान विमान में चालक दल के पांच सदस्य मौजूद थे। कराची की निजी एयरलाइन के2 एयरवेज का मालवाहक विमान (बोइंग 737) को मंगलवार की रात शारजाह से कराची की उड़ान के दौरान तेजी से नीचे आते और अचानक दिशा बदलते देखा गया, लेकिन इसके बाद वह रडार से गायब हो गया था। बुधवार को बलूचिस्तान तट पर ओरमारा से 53 समुद्री मील दक्षिण में विमान का मलबा मिला। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, चालक दल के लापता पांच सदस्यों का कोई पता नहीं चला है।‘पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी’ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी का गहरे समुद्र में खोजबीन और तलाश अभियान जारी है।

स्पेन के जंगल में लगी आग; 12 लोगों की मौत

मैड्रिड/एपी। स्पेन के जंगल में लगी आग ने शुक्रवार तड़के तक 12 लोगों की जान ले ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आग लगने की इस घटना को स्पेन के इतिहास के सबसे घातक दावानल में से एक बताया जा रहा है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल दक्षिणी प्रांत अल्मेरिया में लगी इस आग में कई लोगों के शव जली हुई गाड़ियों के अंदर मिले। माना जा रहा है कि आग से बचकर भागने की कोशिश के दौरान उनकी मौत हो गई। अंदालूसिया क्षेत्र के प्रमुख जुआन मैनुअल मोरेनो ने बताया कि आग में आठ लोग झुलस गए हैं, जबकि 23 अन्य लापता हैं। आग पर काबू पाने के लिए 150 दमकलकर्मी और स्पेन की सैन्य आपदा इकाई के 220 सैनिक तैनात हैं।

टेलीग्राम ने भी यूजरनेम फीचर पर सरकार को जवाब सौंपा

नई दिल्ली/भाषा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने भी व्हाट्सऐप के बाद ‘यूजरनेम’ फीचर को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय से मिले नोटिस का जवाब दे दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि व्हाट्सऐप और टेलीग्राम की तरफ से दी गई प्रतिक्रियाओं का फिलहाल सरकार परीक्षण कर रही है। इन त्वरित संदेश मंचों के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर के तहत उपयोगकर्ता अपना फोन नंबर साझा किए बगैर भी एक-दूसरे से संवाद कर सकते हैं। व्हाट्सऐप ने बृहस्पतिवार शाम को सरकार को अपना जवाब सौंप दिया था।

11-07-2026 सूर्यास्त 6:39 बजे	12-07-2026 सूर्योदय 5:51 बजे
BSE 77,569.39 (+827.57)	NSE 24,206.90 (+244.11)
सोना 15,108 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 234,000 रु. प्रति किलो

स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा स्वागत किया गया।

‘मानव-वन्यजीव संघर्ष संरक्षण एवं विकास की राह में बहुत बड़ी चुनौती’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव भारत के सामने संरक्षण से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मंत्री ने कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं। उद्घाटन के बाद ’इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव’ पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। देश भर से वरिष्ठ नीति-निर्माता, वन प्रबंधक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और संरक्षण से जुड़े लोग इंसानों एवं वन्यजीवों के बीच टकराव को कम करने पर चर्चा के लिए पहुंचे हैं।

यादव ने कहा, ‘‘इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव भारत में संरक्षण और विकास से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानी गतिविधियों के बढ़ने, जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव और वन्यजीवों के पर्यावास घटने की वजह से इंसानों और जंगली जानवरों का आमना-सामना बढ़ गया है। हमारा नज़रिया समाधान खोजने वाला होना चाहिए... जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाए।’’

मंत्री ने भरोसा जताया कि यह नया उत्कृष्टता केंद्र बाघों, तेंदुओं और हाथियों के साथ इंसानों के टकराव की घटनाओं को रोकने के लिए एक रणनीति बनाएगा। उन्होंने कहा कि इंसानों और जंगली जानवरों के आमना-सामना होने की स्थिति से निपटने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा, इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव से निपटने के लिए इलाके एवं जानवरों की प्रजातियों के हिसाब से खास उपाय करने की ज़रूरत है। इससे समाज में फैली घबराहट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

ईसाई संगठनों में एफसीआरए विधेयक वापस लेने का आग्रह किया

नईदिल्ली/भाषा। देश के प्रमुख ईसाई संगठन ‘कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया’ (सीबीसीआई) ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री से प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने का आग्रह किया और कहा कि इस विधेयक और हाल में अधिसूचित नियमों के कुछ प्रावधान धर्मार्थ संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

सीबीसीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह को सौंपे गए ज्ञापन में सरकार से प्रस्तावित संशोधन विधेयक और हाल में अधिसूचित नियमों को वापस लेकर सभी संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श के बाद उन्हें नए सिरे से तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

‘एक देश, एक चुनाव’ की व्यवस्था 2029 तक लागू होने की संभावना : संयुक्त समिति प्रमुख

पी.पी. चौधरी ने दावा किया कि अब तक जिन नागरिक संस्थाओं के हितधारकों से परामर्श किया गया है, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का मकसद बार-बार होने वाले चुनाव से होने वाले अनुमानित सात लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान को रोकना है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों की समीक्षा कर रही समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है जिससे ‘एक देश, एक चुनाव’ सुधार को 2029 के आम चुनाव तक पूरी तरह लागू किया जा सके। गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक से इतर समिति के सदस्य पी.पी. चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अब तक जिन नागरिक संस्थाओं के हितधारकों से परामर्श किया गया है, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का मकसद बार-बार होने वाले चुनाव से होने वाले अनुमानित सात लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान को रोकना है। समिति ने गोवा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा शुरू की। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत से हुई जिसमें एक साथ चुनाव कराने में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर उनकी राय मांगी गई।

चौधरी ने कहा, ‘‘हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अनौपचारिक बातचीत की जो गोवा के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने इस बात पर चर्चा की कि ‘एक देश, एक चुनाव’ को कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें क्या चुनौतियां हैं और सभी को स्वीकार्य संतुलन बनाए रखते हुए उन चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि समिति ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों का दौरा किया है, जहां उसने संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक संस्थाओं, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत की। राजस्थान के पाली से सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने कहा कि जिन लोगों से सलाह ली गई उनमें से अधिकतर लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पाया है कि लगभग 99 प्रतिशत पक्षकारों, खासकर नागरिक संस्था और विभिन्न संगठनों के लोग एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अब कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसे सभी राजनीतिक दल स्वीकार करें।’’ इसे लागू करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समिति कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक यह सुधार लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल और मुख्यमंत्री अपनी चुनावी प्रक्रिया के समय को एक साथ करने पर स्वेच्छा से सहमत हो जाते हैं तो उससे पहले भी कुछ राज्यों को इस व्यवस्था के तहत लाने की संभावना है।

‘वंदे मातरम’ ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया : राधाकृष्णन

शिमला/भाषा। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि ‘वंदे मातरम’ ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया और साहस, त्याग तथा आशा का संचार कर स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। वह शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) द्वारा आयोजित वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन तथा सरदार पटेल का विजन : अखंडता, एकजुटता और संघवाद’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने केवल रियासतों और भूभागों का ही नहीं, बल्कि देशवासियों के दिलों का भी एकीकरण किया। उन्होंने एक राष्ट्र, एक संविधान और एक साझा भविष्य’ की मजबूत नींव रखी।

चेन्नई में बिग बैश लीग का मैच भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ‘खेल रोडमैप’ का मुख्य आकर्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष एंथनी अल्बानीज के साथ मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर कहा, मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में, चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारत में मैच आयोजित करने वाली किसी भी खेल लीग को निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मिलेंगे।

मेलबर्न/भाषा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए शुक्रवार को ‘खेल सहयोग रोडमैप’ जारी किया, जिसका मुख्य आकर्षण बिग बैश लीग (बीबीएल) के आगामी सत्र का उद्घाटन मैच चेन्नई में खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष बिग बैश लीग का पहला मैच दिसंबर में एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा। यह भारत में आयोजित होने वाला पहला विदेशी क्रिकेट लीग मैच होगा। बिग बैश लीग में आठ टीम भाग लेती हैं और यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय घरेलू क्रिकेट लीग में से एक है। इसे आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष एंथनी अल्बानीज के साथ मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर कहा, मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में, चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारत में मैच आयोजित करने वाली किसी भी खेल लीग को निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मैच दिसंबर में पूरे भारत में आयोजित किए जाने वाले ‘गुड डे नमस्ते’ नामक सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। इस उत्सव में ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक, व्यावसायिक और खेल आयोजन शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बानीज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों के क्षेत्र में ‘सहयोग का रोडमैप’ जारी किया, जिसका उद्देश्य खेल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और खेल उद्योग और निवेश में साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में विक्टोरिया प्रांत की प्रीमियर (प्रधानमंत्री) जैसिंटा एलन, वनडे विश्व कप विजेता पूर्व पुरुष कप्तान स्टीव वॉ और महिला कप्तान लिसा स्टालेकर भी उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख तत्वों के रूप में खेल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संबंधों के बढ़ते महत्व को उजागर किया। इस नई पहल से दोनों देशों के बीच खेल संबंध और मजबूत होंगे तथा विशेष कर क्रिकेट के साथ ही अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

शुक्रवार को जम्मू के राम मंदिर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरते श्रद्धालु।

दो लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा किए बर्फानी के दर्शन

श्रीनगर/भाषा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार तक दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये। उन्होंने कहा कि दोनों मार्गों पर यात्रा सुचारू रूप से जारी है और आने वाले हफ्तों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ यह आध्यात्मिक यात्रा जारी रहेगी। सिन्हा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, आस्था के एक अद्भुत प्रमाण के रूप में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के केवल आठ दिनों में दो लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिये हैं। हर हर महादेव! वार्षिक अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई को बालटाल और पहलगाम के दो मार्गों से शुरू हुई थी तथा इसका समापन 28 अगस्त को होगा।

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

विष बोल

थोड़े से लालच के कारण,
अपवित्र कर रहे क्यों प्रसाद।
मर्यादा करते तार-तार,
फैलाते जन-मन में विषाद।
नेता देते वक्तव्य रोज,
फैलाते नित नूतन विवाद।
फिर से ना हों ऐसी ग़लती,
हों ठोस तरीके अब इजाद।।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद की याचिकाओं पर 13 को सुनवाई करेगा न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिकाकर्ता से मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए बाद की किसी तारीख पर सूचीबद्ध कराने का आग्रह करने को कहा था।

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। सात जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से तीन को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की अनुमति दी थी। अदालत ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय की पुलिस रिमांड मंजूर की थी। इससे पहले 29 जून को स्थानीय अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सोमवार को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर इस मामले से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तीन याचिकाकर्ताओं में से एक नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने घटना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया है। दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें इसी तरह के अनुरोध किए गए हैं। वहीं, तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की है।

इसमें उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है।

इससे पहले न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिकाकर्ता से मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए बाद की किसी तारीख पर सूचीबद्ध कराने का आग्रह करने को कहा था। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज, प्रशासन और कथित वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य कथित अनियमितताओं की जांच कराई जानी चाहिए।

अजय कुमार राय ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को आवश्यक नियामक, निगरानी और ऑडिट तंत्र गठित एवं लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया है, ताकि जनहित की रक्षा हो सके और करोड़ों श्रद्धालुओं एवं दानदाताओं का विश्वास कायम रहे।

पुरी मंदिर प्रशासन के आग्रह पर सीकर में 'असमय' रथयात्रा पर रोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शनिवार को कहा कि पुरी के जिलाधिकारी के पत्र के बाद राजस्थान के सीकर जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को प्रस्तावित ''असमय'' रथयात्रा पर रोक लगा दी है।

पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने कहा कि पुरी के जिलाधिकारी और एसजेटीए के उप मुख्य प्रशासक दिव्यज्योति परिदा के पत्र के आधार पर सीकर के जिलाधिकारी आशीष मोदी ने प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। यह रथयात्रा शुक्रवार को विश्व सनातन धर्म सेवा संस्थान और श्री खाटू श्याम मंडल द्वारा आयोजित की जानी थी। यह आयोजन शास्त्रों में निर्धारित तिथि से पांच दिन पहले प्रस्तावित था, जबकि इस वर्ष रथयात्रा का उत्सव 16 जुलाई को मनाया जाएगा।

एसजेटीए ने कहा कि सीकर प्रशासन ने आयोजकों को सूचित किया कि प्रस्तावित रथयात्रा पंचांग और इस पवित्र पर्व से जुड़ी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए उनसे निर्धारित तिथि से पहले रथयात्रा का आयोजन नहीं करने का अनुरोध किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पत्र मिलने के बाद सीकर के जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं, स्थानीय तहसीलदार ने भी आयोजकों से पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुरूप नहीं होने वाली निर्धारित तिथि पर रथयात्रा का आयोजन नहीं करने की अपील की। पुरी मंदिर प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) समेत कुछ संगठनों द्वारा तय तारीख के अलावा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित किए जाने का विरोध कर रहा है।

एनडीए में तबीयत खराब होने के बाद एक कैडेट की मौत

पुणे/भाषा। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पहले टर्म के एक कैडेट ने शुक्रवार सुबह नियमित शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान तबीयत खराब होने की शिकायत की, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। यहां रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के कार्यालय ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले कैडेट अभिनव बाजपेयी (17) ने 24 जून 2026 को पुणे शहर के पास खड़कवासला स्थित इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लिया था।

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अकादमी में शामिल होने के बाद पहली आधिकारिक पीटी परेड के दौरान सुबह नियमित शारीरिक प्रशिक्षण के समय अभिनव ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और अचानक बेहोश हो गया।

नवीन जिंदल समूह झारखंड में करेगा 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उद्योगपति नवीन जिंदल ने झारखंड में इस्पात, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की शुक्रवार को घोषणा की। जिंदल ने वीडियो संदेश में कहा कि इस संबंध में समूह ने झारखंड सरकार के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि नवीन जिंदल समूह ने राज्य में इस्पात, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश में इस्पात क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इससे झारखंड के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और लगभग 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) व स्थानीय उद्यमियों आदि के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। जिंदल ने कहा कि समूह ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी 30,000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, हम झारखंड की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में 650 करोड़ रुपये निवेश करने का भी प्रस्ताव रखते हैं। झारखंड सरकार के साथ हुए समझौते के बारे में जिंदल ने कहा कि राज्य का औद्योगिक आधार मजबूत है। इसके प्राकृतिक संसाधन, कुशल कार्यबल, रणनीतिक स्थिति और उद्यमशीलता की भावना इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाती है।

सुरंग परियोजना स्थल से 200 मीटर से अधिक दूरी पर हुआ भूस्खलन : कोंकण रेलवे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वायनाड/भाषा। केरल के वायनाड-कोझिकोड सुरंग निर्माण का समग्र ठेका संभाल रहे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को दावा किया कि सात जुलाई को हुआ भूस्खलन खुदाई वाले क्षेत्र से करीब 200 मीटर दूर हुआ था, न कि उस स्थान पर जहां स्वीकृत योजना और नक्शों के अनुसार ढलान को सुरक्षित किया गया था।

कोंकण रेलवे की ओर से जारी एक नोट में दावा किया गया कि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हुआ। ऊंचाई में इस अंतर के कारण संरक्षित ढलान के निचले हिस्सों पर भारी दबाव पड़ा और एक ही झटके में आसपास के पेड़ उखड़ गए तथा मिट्टी बह गई। कोंकण रेलवे ने दावा किया कि घटनास्थल पर जमा मिट्टी और मलबा स्थिर था, लेकिन भूस्खलन के मलबे का बहाव इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

कोंकण रेलवे ने बताया कि जून के मध्य से मानसून शुरू होने के कारण काम पहले ही रोक दिया गया था और उस समय कोई सुरंग निर्माण का कार्य नहीं चल रहा था। घटना के समय सुबह मौके पर केवल तकनीकी कर्मचारी मौजूद थे, जो उस क्षेत्र में ढलान की स्थिति पर नजर रख रहे थे जहां खुदाई से निकली मिट्टी जमा की गई थी। उसने दावा किया कि घटना से पहले जरूरी अस्थायी सुरक्षा उपाय, जल निकासी की व्यवस्था और ढलान की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू किए गए थे।

कोंकण रेलवे का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि परियोजना स्थल पर जमा मिट्टी को अधिकारियों के बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं हटाया गया और इसी वजह से भूस्खलन की तीव्रता बढ़ गई।

यह भूस्खलन सात जुलाई को वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर हुआ था। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है।

सूरत में बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास अभियान शुरू किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सूरत/भाषा। गुजरात सरकार ने सूरत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बुधवार सुबह समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान 358 मिलीमीटर बारिश होने से सूरत में हालात खराब हो गए, जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, सूरत और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के बाद, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास अभियान शुरू किया है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद पैदा हुई गंभीर स्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बृहस्पतिवार देर रात सूरत के जिलाधिकारी कार्यालय में आपातकालीन उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए सभी जिला समन्वय अधिकारी, सूरत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

मोबाइल ऐप 1600 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को नहीं कर सकता ब्लॉक : ट्राई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को कहा कि 1600 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को कोई भी मोबाइल ऐप ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉल सरकार एवं विनियमित संस्थाओं की तरफ से आम लोगों के साथ संवाद के लिए निर्धारित हैं। इसके साथ ही ट्राई ने कहा कि 140 नंबर श्रृंखला से आने वाली कॉल को केवल 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) पंजीकरण के जरिए ही ब्लॉक किया जा सकता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पष्ट किया कि दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) के तहत 1600 श्रृंखला से आने वाली कॉल को टैग, ब्लॉक या फिल्टर करने की अनुमति नहीं है।

ट्राई के मुताबिक, 1600 नंबर श्रृंखला का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जैसे नियामकों के अधीन आने वाली बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए करती हैं। इसके अलावा, सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों से संवाद के लिए इसी फोन नंबर श्रृंखला का इस्तेमाल करती हैं।

इस बीच, कॉलर की पहचान करने वाले ऐप 'ट्रूकॉलर' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि 140 और 1600 श्रृंखला से आने वाली फर्जी (स्पैम) कॉल में काफी वृद्धि हुई है। इन दोनों श्रृंखलाओं से प्रतिदिन आने वाली 5.1 करोड़ से अधिक कॉल को लोग उठाते भी नहीं है। उन्होंने बताया कि 1600 श्रृंखला से आने वाली कॉल को ब्लॉक करने की कार्रवाई में अक्टूबर 2025 से 208 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

'एक देश, एक चुनाव से शासन में स्थायित्व, एवं दीर्घकालिक नियोजन सुनिश्चित हो सकता है'

पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का शुक्रवार को पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था से शासन में ज़्यादा स्थिरता आ सकती है, लंबे समय की नीतिगत योजना बनाना संभव हो सकता है और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा सरकार 'एक देश, एक चुनाव' से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक सुधार पर केंद्र की विचार-विमर्श प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करती है। सावंत ने यह बात संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के साथ बातचीत के बाद कही। इस समिति के प्रमुख भाजपा के लोकसभा सदस्य पी पी चौधरी हैं और समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का परीक्षण कर रही है।

फडणवीस ने नासिक में महात्मा फुले स्वास्थ्य योजना में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी बनायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नासिक जिले में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं हेराफेरी की रकम वसूली जाएगी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह घोषणा विधानसभा में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' और 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' की समीक्षा बैठक में की गई।

फडणवीस ने कहा कि एसआईटी की अगुवाई नासिक के संभागीय आयुक्त प्रवीण गेदम करेंगे तथा इसमें अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और यह जांच दल कथित धोखाधड़ी की पूरी जांच करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी ने 2024-26 की अवधि के लिए जांच की थी, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 16,000 संदिग्ध बीमा दावे और सर्जरी की पहचान की गई थी, इनमें से लगभग 9,500 मामले नासिक जिले से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं के कारण जिले के पांच अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है।

राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के चयन ने दिए नई राजनीतिक दिशा के संकेत

कोलकाता/भाषा। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी अब राज्य की राजनीति में विपक्ष के चुनिंदा नेताओं को साथ जोड़कर व संगठन का विस्तार कर स्थिति को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय व प्रकाश चिक बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हुए और कुछ ही घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। विस चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पहली बार है जब भाजपा ने तृणमूल के पूर्व नेताओं को अपने दल में शामिल किया है।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा वाहन जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर पलटा, छह लोग घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा एक वाहन शुक्रवार को उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर पलट गया। इस घटना में छह श्रद्धालु घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हादसा राजमार्ग के उधमपुर-चेनानी खंड में टोल्डी नाले के पास हुआ जब पहलगाम आधार शिविर जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन सड़क से फिसलकर पलट गया। घायल तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सेना, नागरिक रक्षा, यातायात पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया और उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल पहुंचाया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि एक तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल था और उसे जीएमसी जम्मू भेजा गया जबकि शेष पांच तीर्थयात्रियों की हालत स्थिर है और उनका इलाज जीएमसी उधमपुर में हो रहा है। सिन्हा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''उधमपुर के टोल्डी नाला के पास हुई एक सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट मिली है, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा से आए अमरनाथ जी यात्रा के छह तीर्थयात्री शामिल थे। श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहलगाम आधार शिविर जा रहे थे, तभी उनका वाहन सड़क से फिसल गया।'' सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जम्मू के संभागीय आयुक्त, उधमपुर के उपायुक्त और जीएमसी जम्मू व जीएमसी उधमपुर के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराएं। उपराज्यपाल ने कहा, ''मैं भगवान शिव से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।'' केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद उन्होंने उपायुक्त मिंगा शेरपा से बात की।

प्रयागराज कुंभ मेला में पहुंचने के बाद वायरल हुई लड़की को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश रद्द

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस युवती को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने संबंधी अपना पूर्व आदेश वापस ले लिया है, जो प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान सुर्खियों में आई थी। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पुलिस ने बताया कि युवती का कोई पता नहीं चल सका है। कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आयी युवती के पति के खिलाफ उसका अपहरण करने के आरोप में मामला दर्ज है।

युवती के अधिवक्ता पी एस अनीशाद ने बताया कि पुलिस ने न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस को बताया कि जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। वकील अनीशाद ने कहा कि अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए संपर्क करे, तो उसे सुरक्षा दी जाए। अदालत ने कहा, ''अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।'' पुलिस सुरक्षा का उच्च न्यायालय का आदेश लड़की की उस याचिका पर आया था जिसमें उसने अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस थाने के थानाप्रभारी को निर्देश देने का अनुरोध किया था।

लड़की के पति फरमान पर उसके अपहरण का आरोप है। यह मामला मप्र पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था, जिन्होंने दावा किया है कि वह नाबालिग है। अपनी प्यारी मुस्कान और सुंदर आंखों के कारण सोशल मीडिया में वायरल हुई इंदौर की यह लड़की तब चर्चा में आई थी, जब किसी व्यक्ति ने पिछले साल प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए इस लड़की एक वीडियो साझा किया था।

धोखाधड़ी मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। यह मामला 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान हासिल करने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़ा है। भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा, ''हम इसे खारिज कर रहे हैं।'' निचली अदालत के फ़ैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को इस मामले में पूर्व विधायक को सुनाई गई तीन साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत ने दो अप्रैल को इस मामले में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत ने एक अप्रैल को भारती को भादसं (आईपीसी) की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दोषी ठहराया था।

चिकित्सकों पर हमला : शिवसेना पार्षद, तीन सहयोगियों को 13 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ठाणे/भाषा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके तीन सहयोगियों को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्हें एक सरकारी अस्पताल में दो चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

म्हात्रे को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था, जबकि इस घटना में शामिल उनके तीन साथियों को एक दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में म्हात्रे सोमवार शाम को कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉ. वैभव सालुंखे को थप्पड़ और घूंसा मारते तथा रेजिडेंट मेडिकल अधिकारी डॉ. सृष्टि बाविस्कर के हाथ पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश फैल गया।

बुधवार को गिरफ्तारी के बाद म्हात्रे ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें ठाणे जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पहले उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करने के लिए अदालत से अनुमति का अनुरोध किया था। हालांकि, कल्याण स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के. एस. कटकाडे ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और पुलिस को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया। म्हात्रे को दोपहर के भोजन के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल से अदालत लाया गया।

हुंदै की जहाज निर्माण इकाई को आंध्र प्रदेश में समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने का निमंत्रण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केओएसई) के शीर्ष नेतृत्व से शुक्रवार को मुलाकात की और कंपनी को राज्य में विश्वस्तरीय जहाज निर्माण एवं समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

दक्षिण कोरिया यात्रा के छठे दिन मंत्री ने आंध्र प्रदेश की समुद्री क्षमताओं को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य की लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा, भारत के पूर्वी तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति, संचालित तथा प्रस्तावित गहरे समुद्री बंदरगाहों, विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक अवसंरचना, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक परिवेश एवं निवेशक-अनुकूल नीतियों का उल्लेख किया। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ''लोकेश ने सियोल में एचडी केओएसई के वैश्विक कारोबार निदेशक क्रोन यंगहून और टीम लीडर होंग सुंजून से मुलाकात की तथा कंपनी को आंध्र प्रदेश के समुद्री एवं जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया।'' उन्होंने किया मोटर्स, उसके आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कोरियाई कंपनियों के सफल अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की अपनी क्षमता लगातार साबित की है।

मंत्री ने गूगल डेटा सेंटर, आर्सेलरमित्तल के एकीकृत इस्पात संयंत्र और लड़ाकू विमान विनिर्माण परियोजना जैसे प्रमुख निवेशों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले कुल निवेश का लगभग 25 प्रतिशत आंध्र प्रदेश ने आकर्षित किया है। लोकेश ने एचडी केओएसई को आंध्र प्रदेश में विश्वस्तरीय जहाज निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य के विभिन्न संभावित स्थानों का आकलन करने के लिए आमंत्रित दिया।

मुख्यमंत्री विजय ने करूर भगदड़ को लेकर द्रमुक और पुलिस को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

करूर (तमिलनाडु)। करीब एक वर्ष पहले तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद पार्टी संस्थापक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पहली बार शुक्रवार को करूर पहुंचे और इस घटना को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) तथा पुलिस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक ने 2025 में करूर में हुई भगदड़ की दुखद घटना से ''राजनीतिक लाभ'' उठाने की कोशिश की और उन्हें इस पश्चिमी जिले का दौरा करने से भी रोका। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां आए विजय ने पुलिस की भी आलोचना करते हुए कहा कि उसने 27 सितंबर को टीवीके की सभा के आयोजन स्थल पर उन्हें बढ़ती भीड़ के बारे में न तो आगाह किया और न ही भीड़ के बेकाबू होने पर सभा रद्द करने का कोई कदम उठाया। विजय ने 2024 में टीवीके की स्थापना की थी। विजय ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस हमें बता सकती थी कि भीड़ लगातार बढ़ रही है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। पुलिस के पास सभा रद्द करने का पूरा अधिकार था। लेकिन ऐसा करने के बजाय पुलिस हमें अपनी सुरक्षा में राजमार्ग तक ले गई।

विजय पिछले साल करूर जाकर पीड़ित 41 परिवारों से नहीं मिल सके थे। बाद में उन परिवारों को चेन्नई के पास लाया गया, जहां उन्होंने स्वयं उनसे मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शुक्रवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा था। मैंने मंच से पुलिस का धन्यवाद भी किया था। मुझे उस समय इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई का पता नहीं था। यह सब किसकी जिम्मेदारी थी? किसके निर्देश पर यह सब किया गया?'' विजय ने उस समय सत्ता में रही द्रमुक का नाम लिए बगैर कहा, ''उन्होंने इस त्रासदी से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि करूर भगदड़ से उन्हें काफी पीड़ा हुई।

उन्होंने कहा, ''2025 की करूर भगदड़ में हमारी बहनों ने अपने बच्चों को खो दिया।'' काले रंग के परिधान में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि उनकी पार्टी टीवीके करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''आप (द्रमुक) ने मुझ पर छिपने का आरोप लगाया और मेरे खिलाफ तरह-तरह की बातें कहीं।'' उन्होंने दावा किया कि करूर में भगदड़ की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें वहां नहीं जाने की सलाह दी थी। विजय ने कहा, ''मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो राजनीति में राजनीतिक लाभ कमाने के लिए आया हो। मैं लोगों का आभार व्यक्त करने और उनकी सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। क्या आपको लगा कि मैं भाग जाऊंगा? अगर मुझसे पैसे और जनता में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए, तो मैं जनता को चुनूंगा... मेरे लिए सिर्फ जनता ही महत्वपूर्ण है।''

उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपना लोकप्रिय और बेहद सफल फिल्मी करियर भी छोड़ दिया। विजय ने कहा कि अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में द्रमुक की हार पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, द्रमुक की ऐसी हार सुनिश्चित करें, जिससे वह लंबे समय तक उबर न सके। किसी का नाम लिए बिना विजय ने द्रमुक नेताओं वी. सेंथिल बालाजी और ई. वी. वेलु पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपनी चर्चित टिप्पणी दोहराते हुए द्रमुक को ''बुरी ताकत'' बताया और लोगों से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को करारा जवाब देने की अपील की।

गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी. अशोक कुमार को अग्रिम जमानत दी थी। दोनों ने टीवीके सरकार को अस्थिर करने के लिए कथित तौर पर 35 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। वहीं, पूर्व द्रमुक सरकार में लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री रहे ई. वी. वेलु भी कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

द्रमुक पर हमला करते हुए विजय ने आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में हर सरकारी विभाग से ''पार्टी फंड'' के नाम पर भ्रष्टाचार के जरिए धन वसूला जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नाद्रमुक अब एक कमजोर और अप्रभावी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। विजय ने तमिलनाडु के पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच ''मिलीभगत'' होने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम के सत्ता में आने के दो महीने बाद सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी दफ्तरों में एक पैसा भी रिश्वत नहीं ली जा रही है और लोगों को उनका उचित सम्मान मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुलकर कहें कि वे रिश्वत नहीं देंगे। विजय ने कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो मेरा नाम लेकर उसका विरोध करें। उन्होंने यह दावा भी किया कि उनकी सरकार ने राज्य में 'वोट के बदले नोट' की संस्कृति को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर भी द्रमुक की आलोचना करते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब एम. के. स्टालिन मुख्यमंत्री थे, तब इस संबंध में दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

विजय ने कहा कि वह तमिलनाडु के अधिकारों की पूरी मजबूती से रक्षा करेंगे और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत द्रविड़ आंदोलन के महान नेता सी. एन. अन्नादुरै की जयंती पर की जाएगी। विजय ने विपक्ष के विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, जनता हमारे साथ है। सभा के बाद विजय ने करूर में रोड शो भी किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। विजय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया।

करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

करूर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों के सदस्यों को शुक्रवार को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा, उन्होंने इरोड निवासी के. कंदासामी की पत्नी के. शांति को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उनके पुत्र की मौत 27 सितंबर 2025 को विजय की पार्टी तमिलिगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली के दौरान हुई भगदड़ में हुई थी। इस हादसे में 41 लोग मारे गए थे।

मई में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करूर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। लाभार्थियों को जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय सहायक और चौकीदार जैसे पदों पर नियुक्ति दी गई है। ये नियुक्तियां स्कूल शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, शहरी मामलों, पुलिस, पंजीकरण, नगर पंचायत विभागों तथा करूर कलेक्टर कार्यालय में की गई हैं।

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को 41 मृतकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की अनुमति दी थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि ये नियुक्तियां अस्थायी आधार पर होंगी।

इस अवसर पर लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के. ए. सेंगोट्टैयन, दुग्ध विकास मंत्री सी. विजयलक्ष्मी, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, मुख्य सचिव एम. साईकुमार, करूर के जिलाधिकारी सी. मुथुकुमारन तथा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय एकता के लिए एक-दूसरे की भाषाएं सीखना अहम : राज्यपाल आर्लेकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

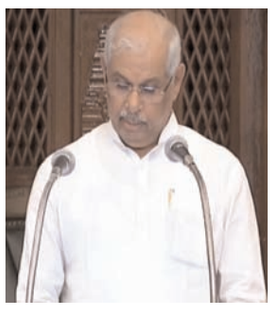

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक-दूसरे की भाषाएं सीखनी चाहिए। राज्यपाल ने सुझाव दिया, ''उत्तर भारत के लोगों को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जैसे तमिल, सीखनी चाहिए, जबकि दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत की कोई एक भाषा सीखनी चाहिए।''

लोक भवन के भारतीयर मंडप में 'चतुर्थ काशी तमिल संगमम, 2025' सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए आर्लेकर ने सवाल किया कि इस तरह भाषा सीखने में क्या कठिनाई हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने में एक जरूरी सेतु का काम करती है। इस कार्यक्रम के दौरान, राज्यपाल ने प्रतियोगिता के विजेताओं, जूरी के सदस्यों और आयोजकों को सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि 'काशी तमिल संगमम' राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकजुटता के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टकोण को दर्शाता है। इस पहल की व्यापक पहुंच का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए 7,000 से अधिक लोग काशी आए हैं। आर्लेकर ने कहा कि काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को उन्होंने खुद अनुभव किया है।

कोई नया अयप्पा संगमम नहीं, भगवान अयप्पा को प्रचार की जरूरत नहीं : टीडीबी प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष के. जयकुमार ने शुक्रवार को कहा कि अब कोई नया अयप्पा संगमम आयोजित नहीं किया जाएगा क्योंकि भगवान अयप्पा को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है।

टीडीबी अध्यक्ष की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पिछले बोर्ड द्वारा तत्कालीन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के समर्थन से ग्लोबल अयप्पा संगमम आयोजित करने के फैसले को लेकर केरल में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। जयकुमार ने आगामी मंडला-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बोर्ड की विशेष बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कोई नया अयप्पा संगमम नहीं होगा। भगवान अयप्पा को प्रचार की जरूरत नहीं है। ग्लोबल अयप्पा संगमम को लेकर वित्तीय विवाद पर उन्होंने कहा कि बोर्ड के लेखा परीक्षक ने ऊरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उस दावे को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें कहा गया था कि आयोजन के लिए छह करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड को जो धनराशि प्राप्त हुई थी, उसका भुगतान पहले ही सोसाइटी को कर दिया गया है और शेष मुद्दों का अलग से निपटारा किया जाएगा। टीडीबी ने वार्षिक तीर्थयात्रा को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों की भी घोषणा की। जयकुमार ने कहा कि इस तीर्थयात्रा सत्र से पूरी व्यवस्था का डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सन्निधानम में उपलब्ध 690 कमरों में से 550 कमरे अब ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि पहले यह संख्या 190 थी।

उन्होंने कहा कि हाउसकीपिंग सेवाओं को आउटसोर्स किया जाएगा तथा आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद शबरि गेस्ट हाउस के निकट 60 अतिरिक्त कमरों वाला नया अतिथि गृह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सन्निधानम (मंदिर परिसर) में श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी, जबकि स्वच्छता संबंधी कार्य 'क्लीन केरल कंपनी' के माध्यम से कराए जाएंगे। जयकुमार ने यह भी कहा कि अन्नदान (निःशुल्क भोजन) के लिए व्यक्तिगत प्रायोजन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, हालांकि संस्थागत प्रायोजन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली तीर्थयात्रा के दौरान जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी, उनके परिवारों को ऑनलाइन कतार बुकिंग से एकत्रित कल्याण कोष से एक-एक लाख रुपये की बीमा सहायता दी जाएगी।

द्रमुक ने मुख्यमंत्री विजय पर करूर में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर करूर में झूठ बोलने और जनता को मूर्ख समझने का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय शुक्रवार को पहली बार करूर पहुंचे। 27 सितंबर 2025 को प्रचार अभियान के दौरान यहां हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। एलंगोवन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विजय के देर से पहुंचने के कारण यह दुखद घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और भोजन व पानी की कमी के कारण कई लोग बेहोश हो गए थे।

एलंगोवन ने कहा कि विजय को दोपहर 12 बजे भाषण देना था, लेकिन वह शाम 7:30 बजे पहुंचे थे, इस वजह से लोगों को कई घंटे तक तेज धूप में इंतजार करना पड़ा। द्रमुक के नेता ने रास्ते में भीड़ के कारण देरी होने की विजय की दलील को बड़ा झूठ बताया। एलंगोवन ने कहा, सामान्य समझ वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि अगर लोगों को तेज गर्मी में बिना भोजन और पानी के छोड़ दिया जाए तो वे बेहोश हो जाएंगे। तत्कालीन द्रमुक सरकार ने करूर अस्पताल में भर्ती 100 लोगों में से 60 लोगों की जान दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर बुलाकर बचाई। लेकिन 41 लोगों को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि उनके शरीर तेज गर्मी और थकावट सहन नहीं कर सके। यह उस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था।

द्रमुक नेता ने विजय के समर्थकों की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ सिर्फ विजय की एक झलक देखने में लगी थी। उन्होंने कहा कि बेहोश लोगों की मदद करने या उन्हें पानी देने के बजाय कुछ समर्थक उनके ऊपर से होकर निकल गए। एलंगोवन कहा कि पर्याप्त पुलिस सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ में हर व्यक्ति के साथ एक पुलिसकर्मी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यह घटना दंगों की नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण हुई थी। मुख्यमंत्री विजय द्वारा द्रमुक सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर एलंगोवन ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के अंदरूनी विवादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और महासचिव ने पार्टी के वकीलों की नियुक्ति के लिए एक लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की रिश्वत ली। एलंगोवन ने कहा, ये आरोप हमने नहीं लगाए। उनकी अपनी पार्टी के एक वकील अदालत गए हैं। अगर विजय से इस बारे में पूछा जाए, तो शायद उनके पास इसका जवाब होगा। करूर भगदड़ से प्रभावित 32 परिवारों को नियुक्ति पत्र देने के बारे में पूछे जाने पर द्रमुक नेता ने इसे करूर उपचुनाव को ध्यान में रखकर किया गया दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि अदालतें पहले भी ऐसे हादसों में सरकारी नौकरी देने के खिलाफ फैसला दे चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य मर गया हो, उसकी मदद करना समझ में आता है, लेकिन यह कदम सिर्फ मतदाताओं को खुश करने के लिए उठाया गया है, ताकि आगामी उपचुनाव में वे विजय की पार्टी के खिलाफ नाराजगी न दिखाएं। एलंगोवन ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक गुप्त सहयोगी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक वर्ष 1972 से, यानी पिछले 54 वर्षों से तमिलनाडु में एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।

एसएचजी ऋण धोखाधड़ी मामले में केनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक व नौ कर्मचारी बर्खास्त

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

थेनी। तमिलनाडु के थेनी जिले में फर्जी महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के ऋण खातों से जुड़े 14 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का पता चलने के बाद केनरा बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक और नौ अन्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। इसने बताया कि आरोप है कि यह धोखाधड़ी जिले में बैंक की दो शाखाओं में की गई, जहां इस मामले के मुख्य आरोपी कार्तिक शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में चिन्नामनूर के निकट स्थित ओडाईपट्टी शाखा में अनधिकृत लेन-देन के माध्यम से 12 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का पता चला था। उन्होंने बताया कि इसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा की गई आंतरिक जांच में पता चला कि इसी तरह के तरीके का इस्तेमाल करके कूलायनूर शाखा में दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का गबन किया गया था, जहां कार्तिक पहले कार्यरत थे। आंतरिक जांच में यह पुष्टि हुई कि कार्तिक ने दस्तावेजों में कथित रूप से जालसाजी की और फर्जी प्रोफाइल बनाए, ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार समूहों के लिए निर्धारित निधि और ऋणों को अवैध तरीके से मंजूर किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका के चलते, बैंक अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ाया और पाया कि करोड़ों रुपये की इस धोखाधड़ी में बैंक के नौ अन्य कर्मचारी कथित रूप से मिलीभगत कर रहे थे। केनरा बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक इंदिरा द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद, थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में व्यापक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस वर्तमान में बैंक के रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तविक खाताधारकों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है।

सेंसर बोर्ड ने विजय की फिल्म 'जन नायकन' में 'टीवीके' और 'न्यू इंडिया' संदर्भ हटाने को कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली/भाषा। सेंसर बोर्ड ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म ''जन नायकन'' के निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे 'टीवीके' और 'न्यू इंडिया' के जिक्र को 'म्यूट' करें या उनमें बदलाव करें, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के जमीन पर गिरने वाले दृश्य को भी हटा दें। फिल्म प्रमाणन आदेश से यह जानकारी मिली। एच. विनोद द्वारा निर्देशित फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र मिला है। फिल्म के लिए जारी आदेश में 12 बदलाव करने को कहा गया है, जिनमें संवाद को 'म्यूट' करना, दृश्यों में बदलाव और कुछ दृश्य हटाना शामिल है। फिल्म का प्रमाणन लगभग सात महीनों तक अटका रहा और यह कानूनी कार्यवाही तथा पायरेसी से जुड़े विवाद का केंद्र बनी रही।

अभिनय की दुनिया छोड़ने और सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला करने के बाद विजय ने फरवरी 2024 में पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (टीवीके) बनायी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के आदेश में अलग-अलग बदलावों के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। सीबीएफसी के निर्देशों के तहत, फिल्म निर्माताओं से कहा गया है कि वे किताब के आवरण पर बीआर अंबेडकर को दिखाने वाले दृश्य में बदलाव करें। ''अंबेडकर सत्तम... टीवीके सत्तम'' शब्दों वाले संवाद को बदल दिया गया है, और फिल्म में जहां भी टीवीके' का जिक्र आया है, उसे 'म्यूट' कर दिया गया है या उसमें बदलाव किया गया है।

सीबीएफसी ने राष्ट्रीय ध्वज के जमीन पर गिरने वाले दृश्यों को हटाने, बच्चे के जलने वाले दृश्यों को बदलने और जिला कलेक्टर के कार्यालय के बैज या निशान को अपमानजनक तरीके से नीचे गिराने वाले दृश्य को हटाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा, 'भागवतम' और 'रंगनाथर' जैसे धार्मिक शब्दों को म्यूट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, दो अपशब्दों को भी हटाने का निर्देश दिया गया।

इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 10% बढ़कर 3,273 करोड़ रु. पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 10 प्रतिशत बढ़कर 3,273 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चेन्नई के इस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में 2,973 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया था। बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 20,724 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में 18,721 करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2026-27 में बैंक को ब्याज से होने वाली आय भी बढ़कर 18,090 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 16,283 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 17 प्रतिशत बढ़कर 7,435 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 6,359 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि में परिचालन लाभ बढ़कर 5,557 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 4,770 करोड़ रुपये था।

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) जून 2026 के अंत तक घटकर कुल कर्ज का 1.86 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले वर्ष 3.01 प्रतिशत थी। शुद्ध एनपीए भी 0.18 प्रतिशत से घटकर 0.15 प्रतिशत रह गई।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते है। निविदा संख्याः एस.एण्ड.टी/बी.के.एन-2026-27-11; **कार्य का नाम व स्थानः** बीकानेर डिवीजन के रतनगढ़-बीकानेर सेक्शन (34 नग) में पीएसआर हटाने के लिए संकेत एवं दूरसंचार से संबंधित कार्य। **अनुमानित लागत मूल्य रू.:** 14495790.42; **बिड सिक्योरिटी:** 2,89,900/-; **निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समयः** 31.07.26 को 15.00 बजे तक; वेब साइट जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाऊनलोड किया जा सकता है: www.ireps.gov.in

986-PH/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

'सहकार से समृद्धि' की मिसाल बना राजस्थान : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारिता को साधन बनाकर समृद्धि की मिसाल पेश की है, जिसका असर धरातल पर नजर आ रहा है। सहकारिता क्षेत्र की राष्ट्रीय योजनाएं हों या फिर कोई नवाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश अन्न भंडारण क्षमता, ई-पैक्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एम-पैक्स के गठन जैसी कई योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। बीते ढाई वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता मॉडल को लागू करने में कई प्रदेशों को पीछे छोड़ने के साथ ही मुख्य कार्यों में प्रथम स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में प्रदेश में 200 गोदाम स्वीकृत हुए हैं, इनमें से 120 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना के तहत तीन साल में राजस्थान में भंडारण क्षमता में कुल 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय सहकारी योजनाओं को प्रमुखता के साथ धरातल पर उतारने में राजस्थान ने अपनी खास पहचान बनाई है। यही कारण है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 जुलाई 2026 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में राजस्थान प्रमुखता से छाया रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास और 50 गोदामों का लोकार्पण किया गया। वहीं, राज्य भंडारण निगम को 100 गोदामों का हस्तांतरण भी किया गया।

राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है कि सहकारिता की लौ गांव-ढाणियों में जल रही है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। प्रदेश में 42 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8 लाख 90 हजार नए सदस्य जोड़कर सहकार परिवार को ओर मजबूत किया गया है।

तकनीक के बढ़ते दौर में सहकारिता को भी आधुनिकता के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के साथ ई-पैक्स के रूप में तेज गति से विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में चिह्नित 6 हजार 781 पैक्स में से 5 हजार 646 ई-पैक्स बनाए जा चुके हैं, जिनके जरिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन हुए हैं, जो देश के कुल ट्रांजेक्शन का लगभग एक तिहाई होने के साथ सभी राज्यों से ज्यादा हैं। हर पंचायत में सहकारी समिति गठन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक 5 हजार 279 नई बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इनमें 1 हजार 977 एम-पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रदेश की लगभग 4 हजार 875 पैक्स तीन या उससे अधिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। इनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाई जा रही है। इस अभियान में भी राजस्थान 6 हजार 753 पैक्स के आंकड़े के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।

राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में लागू किया गया सहकारिता मॉडल ग्रामीण आत्मनिर्भरता के साथ ही महिला सशक्तीकरण का माध्यम भी बना है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध संघों से जुड़े नये सदस्यों की संख्या में 70 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि लगभग 9 लाख 40 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों में 4 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं डबल इंजन सरकार के प्रयासों से घाटे में चल रहे डेयरी संघ भी अब लाभ कमा रहे हैं। पिछले दिनों दर्ज किया गया 10 हजार करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर आरसीडीएफ व जिला दुग्ध संघों के 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है।

सत्ता के अहंकार में सरकार इतिहास के तथ्यों को तोड़-मरोड़ रही है : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबों में कथित बदलाव को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि जिस विचारधारा का देश के स्वाधीनता संग्राम से कोई सरोकार नहीं रहा, जिसने आजादी की लड़ाई में हथियार तो क्या एक तिनका तक नहीं उठाया, वो आज सत्ता के अहंकार में आकर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही है।

उन्होंने एक बयान में कहा, एनसीईआरटी की कक्षा आठ की किताबों में किए गए हालिया बदलाव इसी संकीर्ण मानसिकता का हिस्सा हैं।' पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह गलत 'जनमत' बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, यह सरकार आज हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। अपनी कमियों और नाकामियों को सुधारने के बजाय, ये हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों पर छींटाकशी कर गलत 'नैरेटिव' (विमर्श) गढ़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, देश के युवा इस राजनैतिक दुष्प्रचार और गौरवशाली इतिहास के साथ हो रहे खिलवाड़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं।

ऐतिहासिक यमुना जल समझौता प्रदेश की पेयजल सुरक्षा और समृद्धि का नया अध्याय बनेगा : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बने यमुना जल समझौते से प्रदेश की पेयजल सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी तथा जल संसाधनों के क्षेत्र में दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। यह समझौता राजस्थान के विकास की दृष्टि से गर्व का विषय है इस हेतु मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारीयों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की साथ ही परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किये।

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में यमुना जल हस्तांतरण परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर आयोजित प्रथम समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में परियोजना की विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से डीपीआर के विभिन्न तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने परियोजना के अंतर्गत हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से चूरू के हांसियावास तक पहुंचाने की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने ताजेवाला हेडवर्क्स के स्थान पर विकसित हथिनीकुंड बैराज से जल हस्तांतरण व्यवस्था, पश्चिमी यमुना नहर, पाइपलाइन प्रणाली तथा प्रस्तावित 386 एमसीएम क्षमता के स्टोरेज रिजर्वायर सहित डीपीआर के प्रमुख अवयवों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत लगभग 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली, 386 एमसीएम क्षमता का विशाल जलाशय तथा आधुनिक पम्पिंग एवं जल परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी।

सप्ताह भर मानसून के कमजोर रहने का अनुमान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुक्रवार से कमजोर पड़ने का अनुमान है जिससे भारी बारिश की गतिविधियों पर विराम लगने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार, 10-11 जुलाई से आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में कमजोर मानसून की परिस्थितियां रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।

वहीं, शुक्रवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं-कहीं बादल गरजने एवं झोंकेदार हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 56.0 मिलीमीटर बारिश अजमेर के केकड़ी में हुई। इसके अलावा अंता (बारां) में तीन सेंटीमीटर, बानसूर (अलवर) में तीन सेंटीमीटर, चूरू में तीन सेंटीमीटर तथा लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में दो सेंटीमीटर बारिश हुई।

अमायरा आत्महत्या मामला

नीरजा मोदी स्कूल में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। संयुक्त अभिभावक संघ ने नीरजा मोदी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और नियामकीय अनुपालन में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी स्कूल में पिछले साल नौ वर्षीय छात्रा अमायरा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। संगठन ने शुक्रवार को कहा कि यदि अनिवार्य नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कक्षा चार की छात्रा अमायरा ने पिछले साल एक नवंबर को स्कूल भवन की चौथी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगा दी थी। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

अमायरा के पिता विजय मीणा ने भी कहा कि बेटी की मौत के बाद लगातार सामने आ रहे तथ्य बेहद पीड़ादायक हैं और यदि स्कूल ने शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता, स्टाफ व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य मानकों का पालन नहीं किया है तो निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उनका परिवार सिर्फ अमायरा के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे की सुरक्षा, जवाबदेही और अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ समय पहले पेश किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए स्कूल में शिक्षकों की भर्ती और उनकी योग्यता से जुड़ी बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया।

उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, सीबीएसई निरीक्षण रिकॉर्ड में शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के बीच शिक्षकों की संख्या में बड़ा बदलाव दिखाई दिया और निरीक्षण के दौरान कई नियुक्ति पत्र तथा योग्यता संबंधी रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए। उन्होंने शिक्षकों की योग्यता, स्टाफ व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और स्कूल में नियमों के पालन की स्थिति की स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की। दूसरी ओर, अमायरा के पिता ने आरोप लगाया कि हाल में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में उनकी बेटी स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई दे रही थी और उसकी स्थिति के बावजूद कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मीणा ने कहा कि पुलिस ने हाल ही में मामले में अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा, आरोप पत्र अधूरा प्रतीत होता है। इसमें कक्षा अध्यापिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा भी जोड़ी जा सकती है। साथ ही स्कूल मालिक और प्रधानाचार्य के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 लगाई जानी चाहिए, जबकि आरोप पत्र में यह धारा केवल अध्यापिका के खिलाफ लगाई गई है। मीणा ने कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है। उन्होंने बताया कि पिछले आठ महीनों में मामले की जांच के लिए तीन जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। मीणा ने अदालत से अपील की कि वह आरोप पत्र में मौजूद कमियों का संज्ञान ले, प्रधानाचार्य और स्कूल मालिक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़े और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे।

अलवर में लूटपाट के दौरान बुजुर्ग की हत्या, नेता प्रतिपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के अलवर में 80 वर्षीय व्यक्ति की उनके घर में कथित तौर पर लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बुजुर्ग का शव मिला तो उनके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। पुलिस को शक है कि बृहस्पतिवार को लूटपाट के दौरान उनकी हत्या की गई। मृतक की पहचान दिनेश चंद्र अग्रवाल के तौर पर हुई है जो कोतवाली थाने के खदाना मोहल्ले में अकेले रहते थे।

पुलिस के अनुसार, अग्रवाल रोज शाम को खाना खाने अपने बेटे विकास अग्रवाल के घर जाते थे। जब वह बृहस्पतिवार रात नहीं पहुंचे तो परिवार के सदस्य उनके घर गए और उन्हें एक कमरे में मृत पाया। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। पुलिस ने बताया कि घर में तोड़-फोड़ की गई। अलमारियां खुली थीं और सामान बिखरा पड़ा था। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी पिछले दरवाज़े से अंदर घुसे और घर में रखे लाखों रुपये नकद लेकर भाग गए।

अग्रवाल पुराने नोट बदलने का काम करते थे और आमतौर पर उनके घर पर काफी नकदी रहती थी। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बृहस्पतिवार रात अग्रवाल के घर जाकर शोक-संतप्त परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता का एक और भयावह एवं शर्मनाक प्रमाण है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश के हर जिले से हत्या, लूट, डकैती और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज राजस्थान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपराधी दिनदहाड़े घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और कानून का डर पूरी तरह ख़त्म हो गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है।

लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा का होगा ऐतिहासिक उत्सव : देवनानी

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जन-आकांक्षाओं की संवाहिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा अनुभव और जनसेवा की 75 वर्षों की अविस्मरणीय गाथा है।

देवनानी ने कहा कि सात दशकों से अधिक की इस यात्रा में राजस्थान के विकास, सामाजिक समरसता और बुनियादी सुधारों को गति देने में सदन के प्रत्येक कालखंड के सदस्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा ने समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए हैं, जिन्होंने प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायी उपलब्धियों और जनसेवा के संकल्प का उत्सव है। यह आयोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करेगा

देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर 15 जुलाई, 2026 को विधानसभा भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर सोलहवीं विधानसभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में लोकतंत्र की यात्रा, विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठतम विधायकों का विशेष सम्मान किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि समापन समारोह में राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र का गौरवशाली उत्सव होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला शक्ति, युवा ऊर्जा और जनविश्वास का अद्भुत समन्वय दिखाई देगा।

पूजा

राजस्थान के बीकानेर में योगिनी एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को एक महिला खाटू श्याम मंदिर में पूजा-अर्चना करती हुई।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में स्थापित क्षमता के मामले में राज्य देश में प्रथम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग एवं राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बिजली क्षेत्र सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त ऋण सीमा तथा डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं सी के अंतर्गत 4705 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्य सचिव ने स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय पर पूर्ण करने, वेंडर चयन, स्थापना एवं निरीक्षण की प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय औसत से अधिक दक्ष बनाने तथा बैंक ऋण स्वीकृति से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

समीक्षा में बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब-स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) स्थापित किए जाएंगे तथा इसकी निविदा 13 जुलाई तक जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की दैनिक मॉनिटरिंग, बैंक फाइनेंस, राइट ऑफ वे एवं भूमि संबंधी बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए जिला कलक्टरों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने रूफटॉप सोलर स्थापना की दैनिक गति को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने तथा आगामी सभी लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक ऋण स्वीकृति, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) एवं राज्य सब्सिडी के शीघ्र भुगतान तथा फील्ड अधिकारियों एवं वेंडरों के नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई ।

बैठक में बताया गया कि यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के अंतर्गत 45 सर्किलों के लिए निविदा जारी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव ने तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण करने तथा डिस्कॉमवार एवं सर्किलवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बुजुर्ग दंपति की सड़क हादसे में मौत

कोटा। राजस्थान के बूंदी जिले में बेटे का जन्मदिन मनाने जा रहे बुजुर्ग दंपति की बृहस्पतिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बूंदी जिले के कापरेन कस्बे के रहने वाले कैदार लाल शर्मा (70) और उनकी पत्नी गीता देवी (65) मोटरसाइकिल से कोटा जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान गुड़ला टोल प्लाजा के निकट कोटा-लालसोट मेगा राजनार्ग पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।पुलिस के मुताबिक, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है हालांकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शर्मा सेवानिवृत्त शिक्षक थे जबकि उनके दो बेटे कोटा में रहते हैं और उनमें से एक कोटा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत है।

ओबीसी वर्ग का सर्वेक्षण जिम्मेदारी से करवाए राज्य सरकार : डोटासरा

जयपुर। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को भाजपा नीत राज्य सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के सर्वेक्षण को विश्वसनीय और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से कराने की मांग की। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े अद्यतन आंकड़े जुटाने के लिए राज्यव्यापी डिजिटल सर्वे शुरू किया है। डोटासरा ने सर्वे प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि 'राजधरा सर्वे' मोबाइल एप्लीकेशन में सरकार द्वारा नियुक्त प्रगणकों के लिए उपलब्ध विकल्प को हटा दिया गया है और केवल 'नागरिक' विकल्प ही रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों और प्रगणकों को उनकी आधिकारिक आईडी के माध्यम से आंकड़े अपलोड करने की अनुमति दी जाती तो उसमें सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित होती।

डोटासरा ने कहा, '' इसके बजाय अब कोई भी व्यक्ति नागरिक विकल्प के माध्यम से जानकारी जमा कर सकता है, जिससे आंकड़ों की प्रमाणिकता और सत्यापन को लेकर सवाल उठते हैं।''

‘अयोध्या में आस्था की बात कहने वालों ने कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था।

मुख्यमंत्री अयोध्या में 432 करोड़ रुपये की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री दिवंगत मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा के अनावरण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा, आज अयोध्या में जो लोग आस्था की बात कह रहे हैं, इन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था।

उन्होंने कहा, आप सोचिए, क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें ऐसा करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसा करवा पाएंगी? अगर नहीं, तो फिर अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया? एक अधिकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ नवंबर 2003 की एक घटना का जिक्र कर रहे थे, जब हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर ‘‘हनुमानगढ़ी’’ के बाहर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने

इसकी इजाजत नहीं दी थी। नमाज की घटना के बारे में पूछे जाने पर, उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भाजपा के राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने शुक्रवार को पीटीआई-भाषा से कहा, यह सच है। यह घटना नवंबर 2003 की है, जब रमजान का महीना चल रहा था। बृजलाल ने कहा, उस समय मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार जा चुकी थी। उन्होंने संकेत दिया कि पूरा ‘नमाज़ का प्लान’ तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान बनाया गया था, जो कथित तौर पर समाजवादी पार्टी और वामपंथी झुकाव वाले एक अधिकारी के कहने पर किया गया था। बृजलाल ने बताया कि, नमाज के बाद रोज़ा इफ्तार करने की योजना थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी क्योंकि फैजाबाद (अब अयोध्या) के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव सभरवाल ने साफ़ कह दिया कि वह इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि विरोध के बाद, आखिरकार हनुमानगढ़ी के महंत के घर पर नमाज़ पढ़ी गई, जो मंदिर के पास ही है। बृजलाल ने बताया, असली योजना हनुमानगढ़ी के ठीक बाहर नमाज़ पढ़ने की थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी और वैभवशाली नगरी के रूप में विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप अयोध्या अब सौर ऊर्जा आधारित शहर बन चुका है और देश के प्रमुख शहरों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने राममंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ।

वक्फ बोर्ड जिस जमीन को कब्रिस्तान बोलता था, सपाई वहां से दलितों और गरीबों को उजाड़ देते थे : योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बस्ती/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) पर गंभीर आरोप लगाते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा जब वक्फ बोर्ड किसी जमीन को कब्रिस्तान घोषित कर देता था, तब सपा के लोग वहां रहने वाले गरीबों, दलितों और वंचितों को उजाड़ देते थे।

योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बस्ती जिले में 504 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 77 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा, ‘‘पहले कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा होता था, गरीबों को सताया जाता था, वक्फ बोर्ड केवल कह देता था कि यह कब्रिस्तान है, यह वक्फ की भूमि है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी और दलित, गरीब एवं वंचितों को वहां से उजाड़ दिया जाता था। उजाड़ने का काम सपा के यही लोग करते थे।’’

उन्होंने अन्य विपक्षी दलों पर भी हमला बोलते हुये कहा, ‘‘यह सपा, बसपा और कांग्रेस इनका यही ठेका था।’’ सपा के शासन के दौरान हुए एक वाकये का जिक्र करते हुये योगी ने कहा, ‘‘मैं गोरखपुर से सांसद था। बस्ती के समाजवादी पार्टी के (तत्कालीन) जिलाध्यक्ष के घर के पास कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा हो रहा था।’’

योगी ने कहा, ‘‘तब वह एक दिन वह (सपा जिलाध्यक्ष गुहार लेकर) मेरे पास आया। मैंने कहा कि तुम्हारी सरकार है, तुम कब्जा नहीं रोक पा रहे हो। उसने कहा कि लखनऊ में बैठे लोगों को केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है। इनको हम जैसे लोग दिखाई देते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कार्यकर्ताओं को भेजकर सपा जिलाध्यक्ष की जमीन को कब्जा होने से बचाया। उस वक्त इस तरह की अराजकता थी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘84 कोसी परिक्रमा मखौड़ा धाम से प्रारंभ होती है और देख रहे होंगे कि कितना भव्य कार्य हो रहा है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार 84 कोसी, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी और हमारे समय में डबल इंजन की भाजपा सरकार है, यह रोकती नहीं है, यह रोकने वालों को टोकती है।’’ उन्होंने सरकार को आस्था के सम्मान का श्रेय देते हुए कहा, ‘‘डबल इंजन’’ की सरकार आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और अयोध्या के रिंग रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है।’’

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने एशियाई शेर के तीन शावकों का स्वागत किया

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एशियाई शेरनी महागौरी ने तीन शावकों को जन्म दिया है। पिछले वर्ष महागौरी ने पांच शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से दो जीवित बचे थे। ऐसे में यह लगातार दूसरी सफल प्रजनन उपलब्धि मानी जा रही है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में मंगलवार को महागौरी और महेश्वर की जोड़ी से तीन एशियाई शेर शावकों का जन्म हुआ। प्राणी उद्यान के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि नवजात शावकों को उनकी मां के साथ सुरक्षित प्रसूति बाड़े में रखा गया है। उन्होंने कहा कि शावकों के शुरुआती विकास के लिए उन्हें शांत और निर्बाध वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया

पटना/भाषा। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ‘बंटी’ ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उम्मीदवारी वापस ले ली है। अभिषेक कुमार ‘बंटी’ ने शुक्रवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का उम्मीदवार बनाया था। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि, पारिवारिक कारणों से मैं विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध स्वीकार किया जाए।’’

बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त 3,000 से अधिक शिक्षकों पर गिरेगी गाज

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 3,000 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि इन शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘वर्ष 2006 से 2015 के बीच हुई शिक्षक नियुक्तियों की राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप में 3,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि जांच में फर्जी शिक्षण संस्थानों तथा नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए जाली शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, निगरानी जांच रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों के खिलाफ कई प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं और उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। तिवारी ने कहा, ‘‘इन शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने के बाद उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम करती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस मामले की निगरानी जांच का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था।’’ अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को सेवा अवधि के दौरान दिए गए वेतन और मानदेय की वसूली की भी तैयारी कर रहा है। यह वसूली ब्याज सहित किए जाने की संभावना है। जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षक के रूप में नियुक्त कई अभ्यर्थियों ने फर्जी कॉलेजों द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, जबकि कई अन्य ने नौकरी पाने के लिए जाली शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

सार्वजनिक स्थलों पर उल्फा प्रमुख जैसे ‘असमी क्रांतिकारियों’ की तस्वीर बनाई जानी चाहिए : हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अगर लोग सार्वजनिक स्थानों पर किसी क्रांतिकारी की तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस राज्य से जुड़े लोगों जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा (आई) के प्रमुख परेश बरुआ की तस्वीर बनानी चाहिए, न कि क्यूबा के वामपंथी नेता चे ग्वेरा की, जिनका असम से कोई संबंध नहीं है। शर्मा ने कहा कि वह परेश बरुआ की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते और उनकी निंदा भी करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बरुआ पिछले 30 वर्ष से अपने परिवार से दूर रहकर संघर्ष कर रहे हैं।

करीब एक महीने पहले गुवाहाटी में शहर को सुंदर बनाने के अभियान के दौरान दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के भित्ति चित्र को हटाए जाने से पैदा विवाद का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि अगर असम में किसी क्रांतिकारी की तस्वीर बनानी है, तो वह किसी स्थानीय व्यक्ति की होनी चाहिए। माना जा रहा है कि शर्मा ने यह टिप्पणी जुबिन की पेंटिंग में चे ग्वेरा से जुड़े चित्रों के इस्तेमाल के संदर्भ में कही। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आपको किसी क्रांतिकारी की तस्वीर बनानी है, तो परेश बरुआ की बनाइए। वह पिछले 30 वर्ष से अपना संघर्ष कर रहे हैं। वह सही है या गलत, यह अलग बात है। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। पराग दास की तस्वीर बनाइए।

उन्होंने कहा, हो सकता है मैं परेश बरुआ को स्वीकार न करूं और उनकी निंदा भी करता हूं, लेकिन अगर किसी क्रांतिकारी की तस्वीर बनानी है, तो वह किसी असमी व्यक्ति की होनी चाहिए। परेश बरुआ अलगाववादी संगठन उल्फा (आई) का नेतृत्व करते हैं, जो सशस्त्र आंदोलन चला रहा है। वहीं, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पराग दास की 1996 में गुवाहाटी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि जरूरी अनुमति लेकर सार्वजनिक स्थानों पर भित्ति चित्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन चे ग्वेरा शैली में नहीं। उन्होंने कहा कि वह क्यूबाई क्रांतिकारी नेता चे ग्वेरा के बारे में पहले नहीं जानते थे और तस्वीरें देखने के बाद ही उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा, चे ग्वेरा कौन हैं? मैं क्यूबा गया हूं और उनके बारे में पढ़ाई भी की है। वहां सबसे ज्यादा मादक पदार्थों का कारोबार होता है। हमारा चे से क्या संबंध है? लोग क्यूबा नहीं जा सकते। वहां भारतीय दूतावास सिर्फ एक सौर ऊर्जा स्रोत से चलता है। वहां न सड़कें हैं, न पानी की व्यवस्था। असम की तुलना ऐसे देश से कैसे की जा सकती है? जुबिन गर्ग के भित्ति चित्र को हटाए जाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा, दोनों चित्रकारों ने पुलिस थाने में बयान दिया कि उन्होंने भित्ति चित्र इसलिए हटाया क्योंकि वह जुबिन गर्ग जैसा नहीं लग रहा था। वे न तो मुस्लिम हैं और न ही बांग्लादेशी मियां, बल्कि असमी चित्रकार हैं। जिस ठेकेदार ने यह काम लिया था, वह भी असमी है और तीनों ही जुबिन के प्रशंसक हैं।

शर्मा ने कहा कि सरकार गायक-संगीतकार जुबिन गर्ग का सम्मान करती है और उनके अंतिम संस्कार स्थल का विकास करा रही है, साथ ही उनकी मौत के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत भी गठित की गई है। पिछले वर्ष 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी।

कॉजपा का प्रदर्शन : वांगचुक ने प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाए जाने के खिलाफ किया आगाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि उनके अनिश्चितकालीन उपवास का 13वां दिन होने पर उनकी ‘‘भूख स्थिर’’ हो गई है। उन्होंने जोर दिया कि उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वांगचुक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के लिए सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है।

वांगचुक ने पत्रकारों से कहा, ‘‘आज (उपवास का) 13वां दिन है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। मेरी भूख अब स्थिर हो गई है। शुरुआती दिन मुश्किल होते हैं क्योंकि शरीर उपवास के हिसाब से ढल रहा होता है। थोड़ी थकान है, लेकिन बाकी सब ठीक है।’’ स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में प्रशासन के हस्तक्षेप की संभावना के संबंध में पूछे गए सवाल पर वांगचुक ने कहा कि वह अपनी इच्छा से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और उन्हें वहां से हटाने का प्रशासन के पास कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वे ‘‘मुझे हटाने की कोशिश क्यों करेंगे। मैं अपनी इच्छा से यहां आया हूं और मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर वे मुझे यहां से हटाते हैं, तो यह हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। देश और दुनिया हमारे लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि इस अधिकार का सम्मान जारी रहेगा।’’

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सोमवार तक टला

पटना/भाषा। बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जिसमें पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवकाश पर थे, इसलिए आज आदेश नहीं सुनाया जा सका।

अभिषेक बनर्जी को 15 को आवाज का नमूना देने का अदालती निर्देश

कोलकाता/भाषा।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर डराने-धमकाने वाले बयान देने के मामले में 15 जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी आवाज का नमूना दें। अदालत ने बनर्जी द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने में देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त किया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि वह इस मामले में कार्यवाही रद्द करने और सांसद को कठोर कार्रवाई से संरक्षण देने वाले आदेश को वापस लेने संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई समय से पहले कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार वाली अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष बनर्जी के पेश होने के दौरान उन पर अंडे न फेंके जाएं, या किसी अन्य तरह से परेशान नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि भाषण मामले की जांच के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने के बिधाननगर अदालत के आदेश के खिलाफ बनर्जी की समीक्षा याचिका को, सांसद के वकील के अनुरोध पर वापस ले लिया गया मानते हुए ‘‘खारिज’’ किया गया।

भारी बारिश से हिमाचल की नदियां-नाले उफान पर, नाहन में कई सड़कें बंद

नाहन/भाषा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पिछले 36 घंटों से जारी मूसलाधार मानसूनी बारिश ने जिले के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। काला अंब औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि नाहन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, हालांकि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले की प्रमुख नदियां- टोंस, यमुना, बाता, गिरि और मारकंडा तथा दर्जनों नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी है। बारिश का असर जिले के सड़क नेटवर्क पर भी पड़ा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जिले में कुल 34 सड़कें बंद हैं। इनमें शिलाई उपमंडल की 21, संगड़ाह की आठ, नाहन की चार और राजगढ़ की एक सड़क शामिल है।

इससे पहले दिन में सिरमौर जिले के पांवटा उपमंडल के उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) द्विज गोयल ने मौसम विभाग की भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी के मद्देनजर पांवटा उपमंडल के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया था। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया। हालांकि, अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि शिक्षण संस्थानों के प्रमुख और कर्मचा री प्रशासनिक तथा आपातकालीन कार्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

उत्तराखंड के सात जिलों में बारिश का ’ऑरेंज’ अलर्ट, उफनाई नदी में डूबने से किशोर की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के कारण हुए हादसों में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि जगह-जगह भूस्खलन होने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रदेश की 118 सड़कें अवरुद्ध हो गईं। प्रशासन ने मौसम विभाग के भारी से बहुत भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को देहरादून समेत सात जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके मद्देनजर देहरादून सहित कई जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखे गए।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, हरिद्वार जिले के भगवानपुर में एक किशोर की बरसाती नदी में डूबने से मौत हो गई। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) और पुलिस के तलाशी अभियान के दौरान शुक्रवार तड़के शाहिद (18) का शव बरामद किया गया। एक अन्य घटना में नैनीताल में न्यू पैवेलियन होटल के पास एक विशाल पेड़ गिरने से दो राहगीर मामूली रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह भूस्खलन हुआ, जिससे प्रदेश भर में करीब 118 सड़कें बंद हो गईं। इन मार्गों को खोलने का काम जारी है।

अधिकारियों के अनुसार, उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्यानाचट्टी के पास करीब 100 मीटर सड़क का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी मरम्मत का काम जारी है। वहीं, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगून और नालू पानी में पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिरने के कारण मार्ग बार-बार बाधित हो रहा है। खराब मौसम के बावजूद मलबा हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों समेत कई छोटी नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के हवाले से एसईओसी ने बताया कि उत्तरकाशी और देवप्रयाग में भागीरथी नदी, नंदकेसरी में पिंडर, धारचूला में काली और जौलजीबी में गोरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि, नदियों का जलस्तर अभी चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 191 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

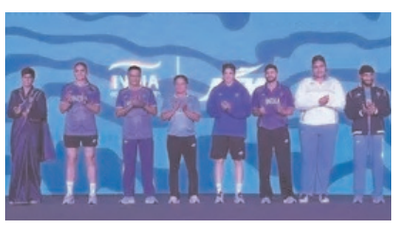

नई दिल्ली/भाषा। खेल मंत्रालय ने 23 जुलाई से ग्लास्गो में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 191 सदस्यीय भारतीय दल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस दल में 126 खिलाड़ी और 51 टीम अधिकारी शामिल हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों की यात्रा एवं अन्य व्यय का वहन सरकार नहीं करेगी। यहां जारी अधिसूचना के अनुसार, दल के भारत लौटने के 30 दिनों के भीतर खेल मंत्रालय को खिलाड़ियों के प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट प्रतियोगिताओं से संबंधित फोटो के साथ प्रस्तुत करनी होगी। भारतीय दल में कुल 126 खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें 78 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया, कोई व्यक्ति अगर आईओए की कार्यकारी समिति, किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) अथवा किसी अन्य खेल निकाय में निर्वाचित पद पर है और उसका नाम टीम अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है तो उसकी यात्रा एवं अन्य खर्च का वहन सरकार नहीं करेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ‘टीम अधिकारी’ की श्रेणी में कोच, सहयोगी स्टाफ, चिकित्सा दल तथा दल के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय दल के प्रमुख रोहित राजपाल ही ऐसे एकमात्र अधिकारी हैं जो आईओए की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। ऐसे में अगर मंत्रालय का यह निर्देश उन पर लागू होता है तो ग्लास्गो में उनके प्रवास का खर्च सरकार वहन नहीं करेगी। मंत्रालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय खेल महासंघों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दलों के सभी सदस्यों का पृष्ठभूमि सत्यापन (बैकग्राउंड जांच) अनिवार्य रूप से कराएं क्योंकि अतीत में कुछ अधिकारियों और खिलाड़ियों के विदेशों में लापता हो जाने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम आवश्यक है। स्वीकृत सूची के अनुसार नीरज चोपड़ा की अगुवाई वाली 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम में 10 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ सबसे बड़ा सहयोगी दल भेजा जाएगा। इस दल के सहयोगी स्टाफ का नेतृत्व मुख्य कोच राधाकृष्णन नायर करेंगे।

सुविचार

अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो, सूरज और चाँद अपने-अपने समय पर ही चमकते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हेराफेरी का खोट, विश्वास पर चोट

दो दशक पहले आम लोगों में यह विश्वास बहुत मजबूत था कि 'अगर अपनी धनराशि को सुरक्षित रखना है तो उसे बैंक में जमा कराएं। अगर उसे ज्यादा सुरक्षित रखना है तो डाकघर से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती।' इस अवधि में साइबर अपराधियों और कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने बैंकों पर लोगों के विश्वास को बड़ी चोट पहुंचाई है। अब डाकघर के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी उनसे चार हाथ आगे निकलने को आमादा हैं। मैसूरु में 44 ग्राहकों के बचत खातों से लगभग 1.3 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सारागुर में तैनात एक डाक सहायक और डाकिए ने ही इतनी बड़ी राशि उड़ा दी! दोनों पर आरोप है कि इन्होंने साल 2022 से 2025 के बीच सुनियोजित तरीके से लोगों के डाकघर बचत खातों से धनराशि निकाली और अपने तथा रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करा दी। यह कितना बड़ा विश्वासघात है! लोग यह सोचकर अपनी मेहनत की कमाई डाकघर को सौंपते हैं कि वह सुरक्षित रहेगी और ब्याज दर के अनुसार उसमें बढ़ोतरी होगी। उक्त दोनों कर्मचारियों ने धनराशि पर ही नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर डाका डाल दिया। मामला सीबीआई तक पहुंचा तो ये पकड़े गए। इन्होंने लॉगिन संबंधी जानकारी का दुरुपयोग कर बचत खातों में सेंध लगाई थी। क्या इन्हें इतना भी नहीं पता था कि अब ऐसे मामलों का खुलासा बहुत जल्दी हो सकता है? सीबीआई जैसी एजेंसी के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने हर ऑनलाइन लेनदेन का रिकॉर्ड देखा होगा। किस यूज़र आईडी से लॉगिन हुआ, किस समय हुआ, किस कंप्यूटर या मोबाइल फोन से हुआ, किस खाते में पैसा गया – जैसे सवालों पर गौर किया होगा। बैंकिंग में मनी ट्रेल बहुत बड़ा सबूत होता है।

आज कंप्यूटर, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, लॉगिन हिस्ट्री, पासवर्ड, फाइलें और अन्य डिजिटल सबूतों के रूप में इतनी कड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें जोड़कर आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन के क्रम का एआई विश्लेषण पूरी पोल खोल सकता है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह बचत खातों में गड़बड़ कर देगा तो जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच सकेंगी। जो भ्रष्ट कर्मचारी खुद को बड़ा होशियार समझता है, वह ऐसे कृत्य के दौरान कई जगह सबूत छोड़ जाता है। हर सबूत को मिटाना उसके लिए संभव नहीं होता है। कौनसी चीज कहां सबूत बन सकती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जब मामला आगे जाता है तो कच्चा चिट्ठा खुलने में देर नहीं लगती है। जिन कर्मचारियों ने यह हेराफेरी की, उन्होंने पहले यही सोचा होगा कि 'हम करोड़ों रुपए आसानी से डकार जाएंगे ... खाता धारकों को तकनीक की ज्यादा जानकारी नहीं है ... जब तक किसी को पता चलेगा, हम करोड़ों में खेल चुके होंगे ... बात फाइलों में दब जाएगी ... जांच होकर किसी नतीजे तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे ... तब तक हम सारी धनराशि खा-पी जाएंगे!' आर्थिक अपराधों के साथ लालच जुड़ा होता है। जब इन्होंने साल 2022 में यह सिलसिला शुरू किया था, तब पकड़ में नहीं आए थे। इसके बाद इनका लालच बढ़ता गया। ये सवा करोड़ रुपए पर हाथ साफ करने के बावजूद नहीं रुके, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। इन्होंने जो धनराशि उड़ाई, उसका उपभोग भी नहीं कर सकेंगे। उसे सरकार वसूल करेगी। इनकी गिरफ्तारी की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा गई। अब मुकदमा झेलेंगे। परिजन परेशान रहेंगे सो अलग। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त मुंह मोड़ लेंगे। इन सबसे क्या मिला? इससे अच्छा यह था कि ईमानदारी से अपनी नौकरी करते और सम्मानजनक जीवन जीते। आज सरकारी नौकरी में वेतन बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके बावजूद किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार की भूख है तो वह याद रखे- यह भूख सोना-चांदी के पहाड़ मिलने पर भी नहीं मिटेगी।

ट्वीटर टॉक

ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज का ज़बरदस्त सेलिब्रेशन देखकर बहुत खुशी हुई। परफॉर्मेंस में पंजाब, तमिलनाडु के कल्चर, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूज़न और वंदे मातरम का ज़बरदस्त वादन दिखाया गया।

-नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में, राजस्थान आज तरक्की का एक नया अध्याय लिख रहा है। खेतों की खुशहाली से लेकर उद्योगों की रफ़्तार तक, सड़क-रेल-ऊर्जाहर सेक्टर 'नए राजस्थान' को देश के विकास की मज़बूत नींव बना रहा है।

-भजनलाल शर्मा

जिस विचारधारा का देश की आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं था, जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक तिनका भी नहीं उठाया, हथियार तो दूर की बात है, वो अब सत्ता के घमंड में इतिहास के पन्नों को तोड़-मरोड़ रही है।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

रेणु का साहस

बिहार के अररिया जिले में जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर वर्ष 1972 में तत्कालीन बिहार सरकार ने उन्हें हर माह तीन सौ रुपये की आर्थिक वृत्ति (वजीफा) देने का फैसला किया, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक खासी रकम थी। उन्हें यह आर्थिक वृत्ति दो सालों तक ठीकठाक मिलती रही। बाद में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन 'संपूर्ण क्रांति' को जब बिहार सरकार ने बल प्रयोग करके कुचलना चाहा तो हालात इस कदर बिगड़े कि मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार की इस दमनपूर्ण कार्रवाई से खिन्न रेणुजी ने तब बिहार के राज्यपाल को भेजे एक पत्र में लिखा था'एक ऐसी सरकार जिसने जनाक्रोश को बलपूर्वक दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया हो, से आर्थिक वृत्ति लेना में अपना अपमान समझता हूं। नैतिकता का तकाजा यही है कि मैं यह वृत्ति लेना बंद कर दूं। इसलिए आप से निवेदन है कि मुझे दी जाने वाली इस वृत्ति को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।'

सामयिक

क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत?

अजय कुमार

मोबाइल : 9335566111

वर्ष 2047 में विकसित भारत बनने का सपना केवल एक सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। यह सपना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, आधुनिक शहरों, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन गुणवत्ता का वादा करता है। लेकिन हर मानसून इस सपने के सामने एक ऐसा आईना रख देता है, जिसमें चमचमाते दावे नहीं, बल्कि पानी में डूबी सड़कें, घंटों का ट्रैफिक जाम, उफनते सीवर, धंसती सड़कें और बेबस नागरिक दिखाई देते हैं। सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी हुई। असली सवाल यह है कि क्या हमारा शहरी ढांचा आज भी सामान्य मानसूनी बारिश झेलने लायक नहीं बन पाया? इस बार मानसून ने पूरे देश को समय पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसानों के लिए यह राहत की खबर थी, लेकिन शहरों के लिए वही पुराना संकट लौट आया। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के बाद अंडरपास जलमग्न हो गए, प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया और कई इलाकों में जनजीवन ठहर गया। गुरुग्राम में करीब 115 मिमी बारिश ने एनएच-48 से लेकर सोहना रोड तक यातायात को घंटों रोक दिया। शहर की पहचान आईटी कंपनियों और ऊंची इमारतों से है, लेकिन हर बारिश यह साबित कर देती है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ड्रेनेज सिस्टम है, न कि मौसम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इससे अलग नहीं है। गोमती नगर, आशियाना, जानकीपुरम, अलीगंज और कई नई कॉलोनियों में हर साल वही दृश्य दोहराया जाता है। जिन सड़कों का उद्घाटन कुछ महीने पहले हुआ होता है, वे पहली तेज बारिश में उखड़ने लगती हैं। कहीं डामर बह जाता है, कहीं गड्ढे बन जाते हैं और कहीं पूरी सड़क धंस जाती है। शहर का विस्तार तो तेजी से हुआ, लेकिन जलनिकासी की योजना उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। नई कॉलोनियां बसती रहीं, पर यह नहीं सोचा गया कि बरसात का पानी आखिर जाएगा कहां?समस्या की जड़ केवल भारी वर्षा नहीं, बल्कि हमारी विकास की सोच है। भारत में सड़क बनने से पहले ही उसके दोबारा खोदे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। आज सीवर लाइन बिछेगी, कुछ महीने बाद गैस पाइपलाइन डलेगी, फिर बिजली की केबल जाएगी, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। हर विभाग अलग काम करता है, लेकिन किसी के पास साझा योजना नहीं होती। परिणाम यह होता है कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनी सड़कें बार-बार टूटती हैं और अंततः नागरिक को घटिया निर्माण की कीमत चुकानी पड़ती है। विकसित देशों में पहले भूमिगत उपयोगिताओं की समेकित योजना बनाई जाती है, उसके बाद सड़क बनती है। भारत में अक्सर सड़क पहले बनती है और योजना बाद में खोजी जाती है।

इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी जवाबदेही की है। नगर निगम नालों की सफाई का दावा करता है, लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण का, विकास प्राधिकरण आधुनिक कॉलोनियों का और जल संस्थान सीवर सुधार का। लेकिन जब बारिश होती है तो हर विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। आखिर पहली बारिश में सड़क धंसने पर कितने अभियंता निलंबित होते हैं? कितने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है? कितने अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है? शायद ही कोई उदाहरण जनता को याद हो। यही कारण है कि हर साल वही गलती दोहराई जाती है और हर बार नए वादे कर दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार इस संकट की सबसे मजबूत जड़ है। यदि सड़क की आयु दस वर्ष होनी चाहिए और वह एक वर्ष में टूट जाए, तो यह केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की बर्बादी है। यदि नालों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पहली बारिश में पानी सड़कों पर भर जाए, तो इसका अर्थ साफ है कि या तो काम ईमानदारी से नहीं हुआ या निगरानी पूरी तरह विफल रही। विकास का सबसे बड़ा दुश्मन संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि संसाधनों का गलत उपयोग है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत की शहरी आबादी 2050 तक लगभग 95 करोड़ तक पहुंच सकती है और तब तक आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे का आधे से अधिक हिस्सा अभी बनाया जाना बाकी है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि यदि शहरों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप तैयार नहीं किया गया तो केवल शहरी जलभराव से ही हर वर्ष अरबों डॉलर का नुकसान होगा। दिल्ली और लखनऊ उन 24 शहरों में शामिल हैं, जिनका अध्ययन इस रिपोर्ट में किया गया। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। अब कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शहरों ने अपने प्राकृतिक नाले, तालाब, पोखर और वर्षाजल के रास्ते स्वयं खत्म कर दिए हैं। जहां पानी को जमीन में उतरना था, वहां आज कंक्रीट है। जहां जलनिकासी का रास्ता था, वहां बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं। जब प्रकृति का रास्ता बंद होगा, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा और उसका पहला पड़ाव हमारी सड़कें ही बनेंगी।

विकसित भारत का अर्थ केवल बुलेट ट्रेन, मेट्रो या एक्सप्रेसवे नहीं है। विकसित भारत वह होगा जहां किसी गर्भवती महिला की एम्बुलेंस बारिश के कारण जाम में न फंसे, जहां स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी से होकर न गुजरें, जहां व्यापारी का कारोबार जलभराव से बंद न हो और जहां पहली बारिश के बाद लोग सोशल मीडिया पर डूबी हुई राजधानी की तस्वीरें साझा करने को मजबूर न हों।अब समय केवल घोषणाओं का नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने का है। हर शहर का वैज्ञानिक ड्रेनेज मास्टर प्लान अनिवार्य होना चाहिए। सड़क निर्माण से पहले सभी उपयोगिता एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए। ठेकेदारों को गुणवत्ता की कानूनी गारंटी देनी होगी। पहली बारिश में सड़क टूटे तो भुगतान रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो।

शहरों के पुराने तालाब, नाले और वर्षाजल मार्ग पुनर्जीवित किए जाएं। नगर निकायों का सामाजिक और तकनीकी ऑडिट नियमित रूप से हो। जब तक भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार नहीं होगा, तब तक हर मानसून विकास के दावों को बहाकर ले जाएगा। 2047 दूर नहीं है। हर गुजरता मानसून हमें याद दिला रहा है कि विकसित भारत का रास्ता संसद की घोषणाओं से नहीं, बल्कि शहर की उस सड़क से होकर जाता है जिस पर आम नागरिक रोज चलता है। यदि दिल्ली, लखनऊ और देश के दूसरे शहर हर वर्ष पहली बारिश में ठहर जाते हैं, तो समस्या बादलों में नहीं, हमारी नीतियों में है। विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी सच होगा, जब बारिश राहत का संदेश लेकर आए, भय और बदहाली का नहीं।

नजरिया

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सुधार और सामाजिक संतुलन की ष्टि से एक बड़ा प्रयोग है। बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों के आने से कम से कम उन मामलों में पारदर्शिता आएगी, जहां हिंदू संपत्तियों या विवादित स्थलों का मामला फंसा हुआ है। यह बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाएगा और एकतरफा फैसलों के आरोपों से बचाएगा।

यूपी वक़्फ़ बोर्ड में हिन्दुओं की एंट्री 'ऐतिहासिक न्याय'

संजय सक्सेना

मोबाइल : 9454105568.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक़्फ़ बोर्ड में दो हिंदू (गैर-मुस्लिम) सदस्यों की नियुक्ति के फैसले ने देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर लिए गए इस फैसले को जहां एक पक्ष 'ऐतिहासिक न्याय', पारदर्शिता और बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता में दखल और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। वैसे, नए वक़्फ़ बोर्ड में हिंदू ही नहीं, महिलाओं और पसमांदा समाज के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके तार ज़मीनी विवादों, ऐतिहासिक दावों, वक़्फ़ कानून की असीमित शक्तियों और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार और हिंदू विचारकों का मानना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि एकतरफा फैसलों पर रोक लगाने और वक़्फ़ बोर्ड की कार्यप्रणाली में 'चेक एंड बैलेंस' (संतुलन) स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इसके अनुसार क़ानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि वक़्फ़ बोर्ड किसी हिंदू की ज़मीन या किसी प्राचीन मंदिर पर अपना दावा ठोकता था, तो उस विवाद का निपटारा करने वाली कमेटी में सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। ऐसे में पीड़ित पक्ष (हिंदू) को हमेशा यह मलाल रहता था कि बोर्ड के भीतर उसका पक्ष रखने या समझने वाला कोई नहीं है। दो हिंदू सदस्यों की मौजूदगी से बोर्ड के भीतर एक बहु-सांस्कृतिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होगा। वक़्फ़ एक्ट, 1995 (विशेषकर 2013 के संशोधनों के बाद) के तहत बोर्ड को किसी भी संपत्ति को 'वक़्फ़ की संपत्ति' घोषित करने के बेहद व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। यदि बोर्ड किसी ज़मीन को अपनी संपत्ति मान लेता है, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे दीवानी अदालत नहीं जा सकता; उसे वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी होती है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जब बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, तो उसका स्वरूप पूरी तरह एकतरफा नहीं होना चाहिए, खासकर तब, जब विवाद गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों से जुड़ा हो।

इस पर योगी सरकार और समर्थकों का आरोप है कि दशकों से राजनीतिक दलों ने वक़्फ़ बोर्ड को एक स्वायत्त साम्राज्य की तरह काम करने की छूट दे रखी थी, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। इस व्यवस्था में सुधार करना तुष्टिकरण को खत्म कर 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को धरातल पर उतारना है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विरोध कर रहे मौलानाओं का तर्क है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वक़्फ़ मूल रूप से इस्लाम के 'अल्लाह की राह में दान' के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है। उनका कहना है कि जिस तरह तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में किसी गैर-हिंदू को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह वक़्फ़ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति करना इस्लामी कानूनों और परंपराओं के खिलाफ है।

विपक्षी दलों (जैसे सपा, कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम) का आरोप है कि सरकार वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्ज़ा करने या उसकी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए यह कदम उठा रही है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा करने और बहुसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा मानता है। उनका कहना है कि यदि बोर्ड में कोई विसंगति थी, तो उसे कानूनी सुधारों या मुस्लिम समाज के ही ईमानदार विशेषज्ञों को शामिल करके सुधारा जा सकता था। इस प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसे समझने के लिए उन विवादों पर नज़र डालना ज़रूरी है, जहां वक़्फ़ बोर्ड के दावों के कारण गैर-मुस्लिमों को ऐसा लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के थिरुचेंथुरई गांव में एक बड़ा विवाद सामने आया था। वहां एक हिंदू व्यक्ति जब अपनी कृषि भूमि बेचने गया, तो उसे पता चला कि पूरे गांव की ज़मीन (जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वरर मंदिर भी शामिल है) वक़्फ़ बोर्ड की है। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके पास सदियों पुराने दस्तावेज़ हैं, लेकिन वक़्फ़ के एकतरफा दावे के कारण वे अपनी ही ज़मीन बेचने या ट्रांसफर करने में लाचार हो गए। ऐसे मामलों ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक डर और असंतोष का माहौल पैदा किया।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आम रही हैं, जहां प्राचीन टीलों, सार्वजनिक पार्कों या ग्राम समाज की जमीनों पर रातों-रात मज़ारें खड़ी हो गईं और बाद में उन्हें वक़्फ़ संपत्ति के रूप में दर्ज करा लिया गया। जब स्थानीय हिंदू आबादी या पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, तो बोर्ड के स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी वक़्फ़ एक्ट की पेचीदगियों के कारण कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजमहल से लेकर कई राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों (जो मूल रूप से प्राचीन हिंदू स्थापत्य काल से जुड़ी मानी जाती हैं या एएसआई के अधीन हैं) पर भी समय-समय पर वक़्फ़ बोर्ड द्वारा मालिकाना हक़ या नमाज़ पढ़ने के अधिकार के दावे किए जाते रहे हैं। इन विवादों में मध्यस्थता या निष्पक्ष समीक्षा के लिए बोर्ड के भीतर किसी भी गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व का न होना हमेशा खटकता रहा है।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सुधार और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से एक बड़ा प्रयोग है। बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों के आने से कम से कम उन मामलों में पारदर्शिता आएगी, जहां हिंदू संपत्तियों या विवादित स्थलों का मामला फंसा हुआ है। यह बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाएगा और एकतरफा फैसलों के आरोपों से बचाएगा। उधर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम समुदाय के भीतर फैले अविश्वास को दूर करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सदस्यों की भूमिका वक़्फ़ के धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में दखल देने की न होकर केवल प्रशासनिक, वित्तीय पारदर्शिता और भूमि विवादों के निष्पक्ष निपटारे तक सीमित रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा कर सके। यदि यह निर्णय केवल राजनीति से ऊपर उठकर ज़मीनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का ज़रिया बनता है, तो इसे भविष्य में एक सकारात्मक सुधार के रूप में याद किया जाएगा। वैसे कुछ लोग वक़्फ़ बोर्ड की तुलना राम मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वक़्फ़ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, या फिर वे जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान पर कई रहस्यमय हवाई हमले किए गए, पर पता नहीं किसने किये

दुबई/एपी

अमेरिका की ओर से हमले रोकने की घोषणा के बाद ईरान पर कई रहस्यमय हवाई हमले किए गए लेकिन यह नहीं पता चल सका है कि इन्हें किसने किया। ईरान पर इन हवाई हमलों ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ईरान को आखिर और कौन निशाना बना रहा है। ये हमले बृहस्पतिवार को ठीक उसी समय पर किए गए जब ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को दफनाने की तैयारी कर रहा था। इन हमलों ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया।

देश के धार्मिक नेतृत्व ने हमलों के लिए सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन एक सांसद ने संयुक्त अरब अमीरात को ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को कथित तौर पर समर्थन देने को लेकर चेतावनी दी है।

खाड़ी के अरब देश, जिन्हें 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगातार निशाना बनाता रहा है, उन्होंने शुक्रवार को इन हमलों पर टिप्पणी किये जाने के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ये देश और अमेरिका इस बात पर जोर दे रहे हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) जहाजों की आवाजाही के लिए खुला और मुक्त रहना चाहिए।

ईरान का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होना चाहिए और जहाजों को तेहरान को शुल्क देना शुरू करना चाहिए भले ही दुनिया दशकों से इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानती रही है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बृहस्पतिवार को ईरान के स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे बताया कि उसने हमलों का एक दौर पूरा कर लिया है, जिसमें लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया गया।

इसके कुछ ही देर बाद ईरान के समाचार प्रतिष्ठानों और सरकारी मीडिया ने देश के बुशहर और सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतों, अहवाज और चाबहार शहरों और अन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए गए कई हवाई हमलों और धमाकों की खबर दी। सेंट्रल कमांड ने अतिरिक्त हमलों के बारे में टिप्पणी किए जाने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।

ईरान ने बृहस्पतिवार को हुए इन हमलों के जवाब में मध्य-पूर्व में बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर को निशाना बनाते हुए और भी बड़े पैमाने पर हमले किए। इन चारों देशों में मिसाइल अलर्ट सायरन बजने लगे, जिससे लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। खबर है कि कुवैत में एक व्यक्ति तब घायल हो गया जब वायु रक्षा प्रणाली ने इलाके में आ रहे हमलों को निशाना बनाया। ईरान के हमले के तुरंत बाद, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कुवैत गए ताकि वे तेल से मालामाल इस छोटे से देश के शासक अमीर से मिल सकें।

खाड़ी के अरब देशों ने कतर के विदेश मंत्री से भी बातचीत की क्योंकि कतर, पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच उस अंतरिम समझौते को लेकर बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका मकसद खुली जंग को फिर से शुरू होने से रोकना है। शुक्रवार को ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर इस्माइल कौसारी के हवाले से कहा कि यूएई को अमेरिका के साथ सहयोग करने की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के पीछे यूएई है।

सिर्फ दिखावे के लिए हमें मेकअप करके सुंदर दिखने की जरूरत नहीं : अभिनेत्री जेनिफर गार्नर

नई दिल्ली/भाषा। हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर गार्नर ने खुद को भाग्यशाली मानती हैं उन्हें ''एक खूबसूरत जिंदगी'' मिली है। अभिनेत्री ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी मेकअप वाली तस्वीर साझा करने की कोशिश नहीं करती बल्कि वह सामान्य दिखना पसंद करती हैं। '13 गोइंग ऑन 30', 'घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट' और 'वैलेंटाइंस डे' की अभिनेत्री ने कहा कि वह सामान्य जिंदगी बिताती हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिनेत्री ने कहा, ''देखिए, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करती। शायद हफ्ते में एक या दो बार ऐसा कर पाती हूं। लेकिन जब भी करती हूं, तो आम तौर पर मैं बिना मेकअप वाली तस्वीरें पोस्ट करती हूं। मैं बस वही पहने होती हूं जो मैंने उस समय पहना होता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं... मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसे एकदम परफेक्ट' न दिखाऊं, बस जैसी हूं वैसी ही दिखूं।''

गार्नर (54) ने लॉस एंजिलिस में 'पीटीआई-भाषा' को डिजिटल माध्यम से दिए साक्षात्कार में कहा, ''देखिए मैं 'परफेक्ट' कुक नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे खाना बनाना पसंद है। इसलिए मैं अपने तरीके से दूसरी महिलाओं के इस पहलू को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हूं। मुझे लगता है कि एक-दूसरे के साथ रहने या सामने आने के लिए हमें हमेशा मेकअप या फिल्टर के जरिए खुद को 'एकदम परफेक्ट' या सुंदर दिखाने की जरूरत नहीं है।'' अभिनेत्री 'द फाइव-स्टार वीकेंड' शो में नजर आने वाली हैं। यह शो एलिन हिल्डरब्रांड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है जिसमें वह एक सेलिब्रिटी फूड इन्फ्लुएंसर' का किरदार निभा रही हैं। हिल्डरब्रांड के नॉवेल द परफेक्ट कपल' पर हाल में नेटफ्लिक्स ने एक शो बनाया था।

गार्नर ने कहा कि वह कुछ दिलचस्प और पेचीदा ढूंढ रही थीं, तभी उन्हें हिल्डरब्रांड का 2023 का नॉवेल मिला और वह तुरंत इसकी कहानी से जुड़ गईं।

प्रदर्शन

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म 'सतलुज' पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को अमृतसर, पंजाब में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर नीरू बाजवा बोलीं, हमें साफ-साफ वजह पता चलनी चाहिए

मुंबई/एजेन्सी

पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर निराशा जाहिर की है। फिल्म को रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही हटा दिया गया था। नीरू ने दिलजीत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को यह चुनने का हक है कि वे किसी फिल्म का समर्थन करना चाहते हैं या उसकी आलोचना करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों को यह जानने का हक है कि फिल्म को अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया। नीरू ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैंने 'सतलुज' देखी, भावनाएं निश्चित रूप से जागृत हुईं। एक फिल्म मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह उसके निर्माताओं की आवाज, उनका जुनून, उनका सच और बरसों की कड़ी मेहनत है। किसी के पास भी बिना जवाबदेही के उसे दबाने की ताकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग किसी फिल्म का समर्थन करें या उसकी आलोचना, यह उनका फैसला होना चाहिए। दर्शकों से यह विकल्प छीनना गलत है। हमें इसे देखने, खुद सोचने और यह तय करने का हक है कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है।अगर 'सतलुज' को हटाया गया है तो जनता को सच्चाई जानने का हक है। हमें स्पष्टीकरण चाहिए, खामोशी नहीं। पारदर्शिता कोई विशेषाधिकार नहीं है; यह एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पंजाबी होने के नाते, उन्हें सवाल पूछने का हक है अगर उनकी मातृभूमि की कहानियों को उनसे छिपाया जाता है।अभिनेत्री ने कहा कि हम कुछ खास नहीं मांग रहे हैं। हम सच्चाई, निष्पक्षता और फिल्म को अनुभव करने और अपनी राय बनाने की आजादी मांग रहे हैं। हमारी आवाज मायने रखती है।

ए.आर. रहमान ने की सोनू निगम की आवाज की तारीफ

मुंबई/एजेन्सी

संगीतकार ए.आर. रहमान की आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' में गीत 'ओह तबस्सुम' को सोनू निगम गाएंगे। ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर सोनू निगम के साथ फिर से काम करने पर खुशी जताई। साथ ही उनकी मधुर आवाज की तारीफ भी की। रहमान ने लिखा, फिल्म 'बंटवारा 1947' के गीत 'ओह तबस्सुम' की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे स्टूडियो में सोनू निगम का फिर से स्वागत करके बेहद खुशी हो रही है। गीत जावेद अख्तर ने लिखा है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं और इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस कर रहा है। भाई... आपकी आवाज इतनी रोमांटिक कैसे लगती है? फिल्म 'बंटवारा 1947' के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और शबाना आजमी जैसे कलाकार नजर आएंगे। पहले इस फिल्म का नाम 'लाहौर 1947' था। सनी देओल और राजकुमार संतोषी इससे पहले 'घायल' और 'दामिनी' में भी साथ काम कर चुके हैं।

कहा जा रहा है कि इसकी कहानी असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई' पर आधारित है। यह नाटक बंटवारे को बड़े पैमाने की राजनीति के नजरिए से नहीं, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन से टूटे मानवीय रिश्तों के जरिए दिखाता है। कहानी एक ऐसे हिंदू परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे लाहौर से भारत आने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें एक मुस्लिम परिवार की छोड़ी हुई हवेली मिलती है, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि वहां अभी एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला रह रही है। सोनू निगम ने शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, गजल, कव्वाली, रॉक और पॉप संगीत जैसे कई तरह के गाने गाए हैं।

उन्होंने अपने करियर में 32 से ज्यादा भाषाओं में 6,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मों में उनका पहला गीत 1993 में रिलीज हुई 'आजा मेरी जान' का 'ओ आसमान वाले' था। इसके बाद टीवी धारावाहिक 'तलाश' के गीत 'हम तो छैला बन गए' से उन्हें पहचान मिली। बाद में 'अच्छा सिला दिया', 'संदेशे आते हैं' और 'ये दिल दीवाना' जैसे गीतों ने उन्हें बड़ी लोकप्रियता दिलाई। वर्ष 1999 में उनका एल्बम 'दीवाना' काफी सफल रहा। 2002 में उन्होंने राजकुमार कोहली निर्देशित फैंटेसी एक्शन फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' में भी अभिनय किया था।

अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

नई दिल्ली/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चेक बाउंस के मामलों में अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को बकाया रकम चुकाने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वह अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के आचरण को संदिग्ध बताया और आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। हालांकि, उन्हें इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय भी दिया गया है। जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह चेक बाउंस के सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे जबकि 25 हजार रुपए राज्य को जमा कराए जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव यदि इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है। यह पूरा मामला अभिनेता की फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से जुड़ा है। साल 2010 में इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और तय समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की जा सकी। बाद में भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पहले उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगाई थी और समझौते के लिए समय देते हुए बकाया राशि चुकाने का अवसर भी दिया था। कई बार आश्वासन देने के बावजूद भुगतान पूरा नहीं किया गया। इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अब उनकी सजा को बरकरार रखा है।

फिल्म निर्माण में उतरेंगी सना सईद

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री सना सईद ने बतौर फिल्म निर्माता अपनी पहली फीचर फिल्म 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट पूरा होने पर जश्न मनाया। उनको ड्राफ्ट (कहानी या स्क्रिप्ट का प्रारंभिक मसौदा) मिल गया है। सना सईद 'बियॉन्ड मैजिक स्टूडियोज' के तहत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। अभिनेत्री इस फिल्म में एक्टिंग भी करेंगी। सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए सना ने कहा कि हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ने से उन्हें फिल्म बनाने का अपना सपना आखिरकार बहुत असली लगा। 'कुछ कुछ होता है' की एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे हाथ में एक फीचर फिल्म के 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट है, जिसे हम मेरी प्रोडक्शन कंपनी, बियॉन्ड मैजिक स्टूडियो के तहत बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम है और यह बस शुरुआत है। उन्होंने कहा, फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है और इसमें बहुत कुछ शामिल है जिसे मैं अभी सीख और समझ रही हूं लेकिन हाथ में यह पहला ड्राफ्ट होना बहुत एक्साइटिंग है। मुझे एक्टिंग पसंद है, लेकिन मुझे फिल्म बनाना भी हमेशा से पसंद रहा है। मैं हमेशा से इसका अंदर से हिस्सा बनना चाहती थी। और इसे हाथ में पकड़ना बहुत असली लगता है। यह बहुत असली लगता है।

सना ने कैप्शन में लिखा, जिस चीज पर मैं कुछ समय से चुपचाप काम कर रही थी, वह आज सच हो गई। मुझे एक फीचर फिल्म के लिए अपने 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट मिला। एक स्क्रिप्ट। एक असली स्क्रिप्ट। एक ऐसी फिल्म के लिए जिसमें मैं एक्टिंग करूंगी, जिसे हम सब मिलकर शुरू से बना रहे हैं। जिस चीज का मैंने सपना देखा था, उसे हाथ में पकड़ने पर कैसा महसूस होता है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इसलिए मैंने बस अपने फोन पर बात की।

कल पार्ट 2 आएगा, जिसमें असली कहानी होगी कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी बार शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ा। सना सईद अभी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में रहती हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मशहूर फिल्म कुछ कुछ होता है में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी और बाद में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नजर आईं। इतने साल में, उन्होंने झलक दिखला जा 6, नच बलिए 7, और फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7 जैसे पॉपुलर रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है।

'द इंडिया स्टोरी' का एक और पोस्टर हुआ रिलीज़

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई सामाजिक मुद्दे पर आधारित आगामी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के निर्माताओं ने फिल्म का एक और प्रभावशाली पोस्टर जारी किया है, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। ज़ी स्टूडियोज़ के सहयोग से एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने संभाली है। यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी। कीटनाशक खेती और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों जैसे संवेदनशील विषय को उठाने वाली यह फिल्म एक दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा के जरिए एक बड़े सामाजिक मुद्दे को सामने लाती है। रिलीज़ हुए नए पोस्टर में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े एक तनावपूर्ण और भावनात्मक स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि फिल्म में उनके किरदार एक बड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए कठिन संघर्ष से गुजरते हैं। सब्जी मंडी के माहौल में सेट यह पोस्टर डर, गुस्से और विरोध की तीव्र भावना को दर्शाता है। पोस्टर में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े को एक आक्रोशित भीड़ से घिरा हुआ दिखाया गया है, जहां गुस्साए विक्रेता उन पर उंगलियां उठा रहे हैं और सब्जियां फेंक रहे हैं। कलाकारों के चेहरे पर दिखता डर, हवा में उड़ती सब्जियां और उग्र भीड़ फिल्म में सच सामने लाने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को बखूबी दर्शाते हैं। ऐसे में पोस्टर पर लिखा टैगलाइन स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस फिल्म के मुख्य विषय को और मजबूत करता है। यह एक ऐसे छिपे खतरे की ओर भी इशारा करता है, जो धीरे-धीरे लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है।

इस विषय में निर्देशक चेतन डीके कहते हैं, यह पोस्टर सच बोलने की कीमत को दर्शाता है। जब किसी झूठ पर आधारित व्यवस्था को चुनौती दी जाती है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया अक्सर डर और गुस्से के रूप में सामने आती है।

'द इंडिया स्टोरी' का हर फ्रेम इसी संघर्ष को दिखाने और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया है कि वे क्या खा रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म के सह-निर्माता स्वाति विनायक सैंदाने, अनीता जाधव, विनायक सैंदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी हैं। फिल्म की तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर निशांत भागवत, संगीतकार मंगेश धकड़े, एडिटर आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आज़मी और साउंड डिजाइनर अनमोल भावे शामिल हैं।

राम कपूर का छलका दर्द, बोले-'गौतमी कपूर और मैंने भी इंडस्ट्री में झेला उम्र का भेदभाव'

मुंबई/एजेन्सी

टीवी के लोकप्रिय अभिनेता राम कपूर ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं और दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है। वह अक्सर मनोरंजन जगत के उस सच पर खुलकर बात करते दिखते हैं, जिसके बारे में कलाकार बोलने से बचते नजर आते हैं। इस कड़ी में राम कपूर ने बताया कि इंडस्ट्री में उम्र बढ़ने के साथ कलाकारों को किस तरह नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही बताया कि उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौतमी कपूर भी इसी तरह के दौर से गुजर चुकी हैं। राम कपूर ने यह खुलासा नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के दौरान आकांक्षा चमोला से बातचीत में किया। दरअसल, शो में आकांक्षा चमोला ने राम कपूर से कहा कि वह जल्द ही अपने पति गौरव खन्ना से अलग रहकर अपनी नई शुरुआत करने वाली हैं। ऐसे में उन्हें अपना नया ठिकाना बनाना होगा और करियर को भी नए सिरे से संभालना पड़ेगा। उन्होंने राम से कहा कि इस सफर में उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आकांक्षा की बात सुनकर राम ने बिना किसी झिझक के उनका साथ देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी पूरी टीम को उनकी मदद के लिए लगा देंगे।

बातचीत के दौरान आकांक्षा ने मनोरंजन इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कलाकारों की उम्र को लेकर बहुत जल्दी धारणा बना ली जाती है। जैसे ही कोई कलाकार 35 साल की उम्र पार करता है, उसे यह कहकर अलग कर दिया जाता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। इससे कलाकारों के लिए नए मौके कम होने लगते हैं और करियर पर असर पड़ता है। आकांक्षा ने राम कपूर से बात करते हुए कहा, आप जानते हैं कि लोग हमारी उम्र को अच्छी नजर से नहीं देखते। दुर्भाग्य से जैसे ही कोई कलाकार 35 साल का होता है, उसे यह कहकर अलग कर दिया जाता है कि वह अब बहुत उम्रदराज हो गया है। मुझे इस दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मैं जितना कर सकती थी, उतना किया है। अब उम्मीद है कि आगे भी काम मिलता रहे, ताकि मैं अपनी जिंदगी सुरक्षित बना सकूं।

आकांक्षा की बातें सुनकर राम कपूर ने कहा कि उनकी स्थिति उन्हें अपनी पत्नी गौतमी कपूर की याद दिलाती है। उन्होंने बताया कि गौतमी भी अपने करियर में ऐसे ही दौर से गुजरी हैं और वह इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं।

राम ने कहा, गौतमी और मैंने भी उम्र का भेदभाव झेला है। शुरुआत में गौतमी भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरी थीं। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दौर तुम झेल रही हो, उससे गौतमी भी गुजर चुकी हैं। वह मेरी पत्नी हैं, मेरी दुनिया हैं, मेरा प्यार हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम किस स्थिति में हो। मैं तुम्हारे लिए जितना संभव होगा, उतनी मदद करूंगा।

बता दें कि नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे कई चर्चित चेहरे भी शामिल हैं।

तेरापंथ सभा व तेयुप हनुमंतनगर का सामूहिक दायित्व बोध ग्रहण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के तेरापंथ भवन हनुमंतनगर में मुनिश्री विनीत कुमार जी एवं आकाश कुमार जी के सान्निध्य में तेरापंथ सभा ट्रस्ट एवं तेरापंथ युवक परिषद हनुमंतनगर का सामूहिक दायित्व बोध ग्रहण समारोह जैन संस्कार विधि से सम्पन्न हुआ। सभा के निवर्तमान अध्यक्ष गौतम दक ने नव निर्वाचित अध्यक्ष महावीर देरासरिया को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई, तत्पश्चात अध्यक्ष महावीर देरासरिया ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में हेमराज मांडोत, प्रकाश बोल्या, अमोलकचंद कटारिया, मंत्री रतन कटारिया, सहमंत्री राजेश मारू, महावीर भटेवरा, कोषाध्यक्ष नाथूलाल बोल्या, सहकोषाध्यक्ष प्रकाश गांधी, संगठनमंत्री गौतम कातरेला, मीडिया प्रभारी कमलेश झाबक को शपथ दिलाई। कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की भी घोषणा की गई।

अभातेयुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मांडोत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रोहित कोठारी एवं परिषद निवर्तमान अध्यक्ष स्वरूप चौपड़ा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय कटारिया को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई।

अध्यक्ष विजय ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए उपाध्यक्ष नवरतन बोल्या, गौतम चावत, मंत्री राहुल मेहता, सहमंत्री आकाश मेहता, सहमंत्री रोहित देरासरिया, कोषाध्यक्ष सन्नी रांका, संगठनमंत्री मनोज पोरवाड़ को शपथ दिलाई। परिषद परामर्शक के रूप में महावीर बोल्या, महावीर चावत, महावीर कटारिया, पवन बोथरा, धर्मेश कोठारी सहित कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें शपथ दिलाई।

मुनिश्री विनीत कुमार जी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन में संस्कारों की आवश्यकता होती है।

समाज के कार्यों के साथ साथ अध्यात्म के कार्य भी होते रहने चाहिए व पूरी सक्रियता के साथ कार्य करे। मुनिश्री आकाश कुमार जी ने कहा कि सबसे बड़ा शिक्षक जिम्मेदारी होती है। जो शिक्षा जिम्मेदारी सिखाती है वो और कोई नहीं सीखा सकता। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो इसे समझते हैं और इसे निभाते हैं। चारों संतों ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संबंधित संस्थाओं के अनेक सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हेमराज मांडोत ने किया। मंत्री रतन कटारिया ने धन्यवाद दिया।

अहंकार का त्याग और सद्गुरु का समागम ही आत्मकल्याण का मार्ग : साध्वी प्रियरंजनाश्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां खरतरगच्छीय गणिनी सुलोचनाश्रीजी म.सा. की शिष्या साध्वी प्रियरंजनाश्रीजी म.सा. का शुक्रवार सुबह लुम्बिनी अपार्टमेंट जैन संघ में पदार्पण हुआ। वहां धर्मसभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रियरंजनाश्रीजी म.सा. ने कहा कि अहंकार मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मन में अहंकार, ईर्ष्या और 'मैं' का भाव रहेगा, तब तक कर्मबंधन से मुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने फुटबॉल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार उसमें भरी हवा उसे बार-बार ठोकरें खाने के लिए विवश करती है, उसी प्रकार अहंकार रूपी हवा मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधे रखती है। उन्होंने कहा कि देव, गुरु और धर्म की कृपा से प्राप्त पद, प्रतिष्ठा, सत्ता और संपत्ति तभी सार्थक हैं, जब उनके प्रति श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव बना रहे।

उन्होंने कहा कि 'मैं' और 'मेरापन' का त्याग किए बिना महानता प्राप्त नहीं की जा सकती। अहंकार अपनों के बीच भी दूरी पैदा कर देता है तथा व्यक्ति माता-पिता जैसे उपकारियों के प्रति भी कृतज्ञता भूलने लगता है। उन्होंने कहा कि यदि छोटी-सी धार्मिक विधि भी शुद्धता और विधिपूर्वक नहीं कर सकते, तो परमात्मा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना कठिन है। जीवन में सरलता, सहजता और विनम्रता ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है।

साध्वी प्रियशुभांजनाश्रीजी म.सा. ने कहा कि सद्गुरु का समागम जीवन का दुर्लभ सौभाग्य है। समागम की साधना के बिना सद्गुरु का संयोग प्राप्त नहीं होता और सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्षमार्ग की यात्रा भी कठिन है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ बताया है क्योंकि मनुष्य को जिनवाणी का श्रवण करने की अमूल्य क्षमता प्राप्त है। सच्चा श्रावक वही है, जो श्रद्धा के साथ जिनवाणी सुनकर उसे अपने आचरण में उतारे। उन्होंने रोहिणिया चोर का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि परमात्मा की वाणी का श्रवण उसके जीवन के परिवर्तन का कारण बना। इसी प्रकार श्रद्धा के साथ सद्गुरु की शरण स्वीकार करने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को छोटे-छोटे नियम, प्रत्याख्यान और संतुलित अभिग्रह ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में उन्होंने कहा कि सद्गुरु का अधिकाधिक समागम कर धर्माराधना करने से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।

आर्ट ऑफ़ गिविंग ने आयोजित किया साक्षरता कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कुनिगल । तालुक के तारेदाकुप्पे सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में आर्ट ऑफ़ गिविंग की ओर से साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि आमतौर पर, माता-पिता अपने बच्चों को साक्षरता के लिए दूर-दराज़ के मशहूर मंदिरों में ले जाते हैं और उनसे साक्षरता (लिटरेसी) अभ्यास करवाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन माता-पिता ने अपने गाँव के स्कूल में बड़े पैमाने पर साक्षर होते देखकर बहुत खुशी जताई। इस आयोजन में पारंपरिक कपड़े पहने अभिभावों सहित बच्चों ने खुशी मनाई।

मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से विनायक पूजा और सरस्वती पूजा कर साक्षरता विधि की रस्में पूरी की। हाई स्कूल के हेडशिक्षक मंजूनाथ आचार्य ने बच्चों से कहा कि बच्चों को बड़ा होकर कल्पवृक्ष की तरह दूसरों के लिए छाया बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं।

इस मौके पर ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य शानेगौड़ा ने इस स्कूल को एक वाहन भेंट किया। इस मौके पर बच्चों को किताबें व अन्य पाठ्य सामग्री बांटी गईं। इस मौके पर तारेदाकुप्पे गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर मंजुला, अध्यक्ष रवीश, आर्ट ऑफ गिविंग के प्रदेश अध्यक्ष गुरुप्रसाद, सेतु एंटरप्राइजेज के रविकिरण, नटराजू, समाजसेवी शानैया, विमला केजी विजयलक्ष्मी आदि उपस्थित थे।

इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट और टेबल टेनिस टूर्नामेंट सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। प्रतिभा खेल जिताती है, लेकिन टीम वर्क और बुद्धिमत्ता चैंपियनशिप जिताती हैं। 19 वां जयगोपाल गारोदिया मेमोरियल इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट और 18 वां सीतादेवी गारोदिया मेमोरियल इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट हमारे गारोदिया में गत 8 व 9 जुलाई को आयोजित किया गया था। जिसमें कुल 26 टीमों ने भाग लिया। वॉलीबॉल टीम के विजेताओं को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। उपविजेता को 4,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। जिसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया। टेबल टेनिस टीम के विजेताओं को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। उपविजेता को 1,500 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिला।

समापन समारोह 9 जुलाई दोपहर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मध्य एशियाई वॉलीबॉल संघ के रेफरी समिति के अध्यक्ष एस. बेनी कूंघे थे। मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के पाठ्यक्रम में खेलों के महत्व के बारे में बताया, जिसके बाद पुरस्कार वितरण किया गया। समारोह में न्यासी मेयप्पनजी, शैक्षणिक निदेशक जी. विजयकुमार, जेजीवीवी की प्रधानाचार्या सुश्री एम. उमा और जेजीवी के प्रधानाचार्य श्री वी. राजेश उपस्थित थे।

मैसूरु दशहरा महोत्सव को लेकर बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। मैसूरु में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। शिवकुमार ने शुक्रवार को विधान सौधा सम्मेलन हॉल में मैसूरु के जन प्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक की और मैसूर दशहरा-2026 के आयोजन पर चर्चा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री के. जे. जॉर्ज, शहरी विकास मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्दरामय्या, सांसद यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वोडेयार, विधायक डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, जी. टी. देवेगौड़ा, मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एसएनएन राज लेक व्यू से 9 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। श्रावण मास के अवसर पर एसएनएन राज लेक व्यू अपार्टमेंट्स के निवासियों द्वारा 9 अगस्त को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा प्रातः %:30 बजे चौपाल, एसएनएन राज लेक व्यू फेज-2 से प्रारंभ होगी। यात्रा में श्रद्धालु गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर अपार्टमेन्ट के विघ्नेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिवलिंग का विशेष जल से जलाभिषेक किया जाएगा। शिव भक्त पंजीकरण करवाकर इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों तक इस आयोजन में शामिल होने का निवेदन किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

करूर भगदड़ मामला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने द्रमुक और पुलिस को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

करूर/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने पिछले वर्ष करूर में हुई भगदड़ की दुखद घटना से ''राजनीतिक लाभ'' उठाने की कोशिश की और उन्हें जिले का दौरा करने से भी रोका।

पिछले वर्ष हुई भगदड़ की घटना के बाद पहली बार यहां आए विजय ने पुलिस की भी आलोचना करते हुए कहा कि उसने 27 सितंबर को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की सभा के आयोजन स्थल पर उन्हें बढ़ती भीड़ के बारे में न तो आगाह किया और न ही भीड़ के बेकाबू होने पर सभा रद्द करने का कोई कदम उठाया। विजय ने कहा, पुलिस हमें बता सकती थी कि भीड़ लगातार बढ़ रही है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। पुलिस के पास सभा रद्द करने का पूरा अधिकार था। लेकिन ऐसा करने के बजाय पुलिस हमें अपनी सुरक्षा में राजमार्ग तक ले गई।

मई में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले विजय 2025 में करूर जाकर भगदड़ से पीड़ित 41 परिवारों से नहीं मिल सके थे। बाद में उन परिवारों को चेन्नई के पास लाया गया, जहां उन्होंने स्वयं उनसे मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शुक्रवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा था।

मैंने मंच से पुलिस का धन्यवाद भी किया था। मुझे उस समय इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई का पता नहीं था। यह सब किसकी जिम्मेदारी थी? किसके निर्देश पर यह सब किया गया? विजय ने उस समय सत्ता में रही द्रमुक का नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने इस त्रासदी से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करूर भगदड़ से उन्हें काफी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, 2025 की करूर भगदड़ में हमारी बहनों ने अपने बच्चों को खो दिया। काले रंग के परिधान में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि उनकी पार्टी टीवीके करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण कराएगी। इसके बाद उन्होंने करूर में रोड शो भी किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। विजय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया।

आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक तीन दिवसीय बैठक के लिए बेलगावी में एकत्र हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। देश भर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक शुक्रवार को यहां अपनी सालाना तीन दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक में देश भर में जारी जनगणना प्रक्रिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक' शुक्रवार को यहां सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति में शुरू हुई, जो 12 जुलाई को समाप्त होगी। बैठक में आरएसएस की शाखाओं के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और संघ की पहुंच को और बढ़ाने के लिए शाखाओं की संख्या बढ़ाने की योजना पर चर्चा की जाएगी।

आरएसएस ने एक बयान में कहा कि बैठक में देश भर से सभी सह सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख, कार्यकारी परिषद के सदस्य, प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक भाग ले रहे हैं। संघ के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार, सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के कार्यकर्ता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा संघ से प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

आचार्यश्री विजय कुलबोधिसूरिश्वर म. का चातुर्मास प्रवेश कल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ के तत्वावधान में आचार्य देवेश भुवनभानुसूरिश्वरजी म. के समुदाय के आचार्यश्री वरबोधिसूरिश्वरजी म. के शिष्य आचार्यश्री विजय कुलबोधिसूरिश्वरजी म., पंन्यास ज्ञानबोधि विजयजी म. एवं साध्वीजी श्री पुण्यनिधिश्री म. आदि श्रमण-श्रमणीवृंद का भव्य चातुर्मास प्रवेश रविवार प्रातः श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में सम्पन्न होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर चेन्नई सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, समाज के गणमान्य नागरिकों एवं धर्मप्रेमियों की उपस्थिति रहने की संभावना है। चातुर्मास प्रवेश के उपलक्ष्य में पूनमल्ली हाई रोड स्थित विमलाचल अपार्टमेंट से भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा। यह वरघोड़ा श्री संभवनाथ जिनालय में दर्शन-वंदन के पश्चात एटकिंसन रोड स्थित गौतम किरण परिसर पहुंचेगा, जहां विशाल धर्मसभा आयोजित होगी। धर्मसभा में आचार्यश्री 'माई 5 पावर' विषय पर विशेष प्रवचन देते हुए आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविकास एवं जीवन मूल्यों पर अपने प्रेरक विचार व्यक्त करेंगे। वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ के अध्यक्ष तेजराज कोठारी ने बताया कि चातुर्मास प्रवेश के पावन अवसर पर प्रातःकालीन नवकारसी के लाभार्थी विमलाचल अपार्टमेंट एवं सकल संघ की नवकारसी का आयोजन श्री संभवनाथ जिनालय उपाश्रय में किया जाएगा।

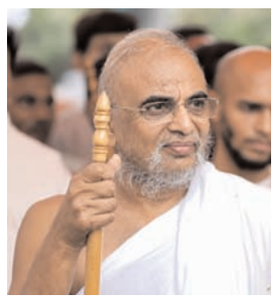

उन्होंने बताया कि भव्य वरघोड़ा एवं नवकारसी के लाभार्थी संघवी वसंतीबाई मंछालाल ताराचंद सोनीगरा मेरमांडवाड़ा परिवार होंगे, जबकि आचार्यश्री के वधामणा के लाभार्थी संघवी नारंगीबाई माणकचंद पूनमचंद चौहान देलंदर परिवार होंगे। सचिव आकाश जैन ने समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से इस पुण्य अवसर पर परिवार सहित उपस्थित होकर धर्मसभा का लाभ लेने तथा चातुर्मास प्रवेश की ऐतिहासिक बेला के साक्षी बनने का आग्रह किया।

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 को अंतरिक्ष के लिए होंगे रवाना

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाखस्तान स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम (अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल) से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आठ महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे मेनन आपातकालीन चिकित्सा के चिकित्सक और अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कर्नल हैं। अमेरिकी वायुसेना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 'ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम' के तहत अफगानिस्तान में अग्रिम मोर्चे पर सेवा दी। इसके अलावा उन्होंने 'हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन' के साथ भी काम किया, जहां वह माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों का इलाज करते थे। मेनन (49) भारत में भी एक वर्ष तक 'रोटरी एंबेसडोरियल स्कॉलर' के रूप में रहे, जहां उन्होंने पोलियो टीकाकरण अभियान के अध्ययन और समर्थन का कार्य किया।

लेडिंज विंग द्वारा बच्चों को शैक्षणिक सामग्री भेट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। महावीर इंटरनेशनल रॉयल चेन्नई के तत्वाधान में लेडीज विंग द्वारा एजी जैन स्कूल के छात्रों को किताब, पेन ,पेंसिल किट एवं स्नेक्स का वितरण किया गया। सदस्या बिंदु पारख के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष में बच्चों को यह शैक्षणिक सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष सज्जनराज मेहता के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र से हुआ।

लेडीज विंग की सुशीला बछावत, प्रिया अंबानी, कल्पना समदड़िया, बबीता-कल्पना बैद, नीलम जैन, पूनम समदड़िया, ललिता कटारिया, स्नेहलता नाहटा एवं स्कूल के सचिव दलजीत सिंह ढढ़ा प्राचार्य जयश्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

राम मंदिर मामले पर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें : कांग्रेस

नई दिल्ली/देहरादून/चंडीगढ़/भाषा। कांग्रेस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जाए तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में अपने अभियान को तेज करते हुए शुक्रवार को कई शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी शनिवार को भी कई शहरों में इसी विषय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पार्टी के इस अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मोर्चा संभाला और संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) राम मंदिर के नाम पर चंदा एकत्र करते रहे हैं।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.